

राहुल गांधी पर एफआईआर से भड़की कांग्रेस, फूँका पुतला



रांची : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड में दर्ज प्राथमिकी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। अलबर्ट एक्का चौक पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूँका।

भाजपा पर राजनीतिक बौखलाहट का लगाया आरोप: प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआइआर भाजपा की राजनीतिक बौखलाहट का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े, वंचित और आम जनता के अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं। इसी कारण भाजपा सरकार उन्हें निशाना बना रही है।

उन्होंने कहा कि भाजपा यह भ्रम न पाले कि एफआइआर और सरकारी दबाव के जरिए राहुल गांधी की आवाज को दबा देगी। राहुल गांधी अकेले नहीं हैं। उनके साथ देश के किसान, युवा, छात्र, आम जनता और करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ कोई कृत्य किया गया है, तो उनके खिलाफ भी तत्काल प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। देश में कानून का राज है, भाजपा का राज नहीं है।

कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने कहा कि राहुल गांधी को निशाना बनाना दरअसल देश की जनता की आवाज को निशाना बनाना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ जितने मुकदमे दर्ज होंगे, जनता के बीच भाजपा सरकार के खिलाफ उतने ही सवाल खड़े होंगे।

सह-प्रभारी डॉ सिरिवेला प्रसाद ने कहा कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज से डर गयी है। जब जनता के सवालों का जवाब देने में सरकार विफल होती है, तब जांच एजेंसियों, पुलिस और मुकदमों का सहारा लेकर विपक्ष को डराने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी डरने और झुकने वाली नहीं है। मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि आज का प्रदर्शन स्पष्ट संदेश है कि संविधान और लोकतंत्र से खिलवाड़ कांग्रेस किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और झारखंड कांग्रेस उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि यह आंदोलन यहीं समाप्त नहीं होगा। जब तक लोकतंत्र और संविधान पर हमला जारी रहेगा, कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की राजनीति देश के मुठों पर जवाब देने की नहीं, बल्कि सवाल पूछने वालों को डराने की राजनीति बन गयी है। कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद: प्रदर्शन में विधायक डॉ रामेश्वर उरांव, पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस नेता बंधु तिकी, शहजादा अनवर, राजेश गुप्ता छोट्टा, रवींद्र सिंह, राकेश सिन्हा, सुरेंद्र सिंह, सूर्यकांत शुक्ला, आलोक दुबे, विनय सिन्हा दीपू, सोनाल शांति, राजन वर्मा, उज्ज्वल तिवारी, सुनील सिंह, राजेंद्र दास, सोमनाथ मुंडा और विजय शंकर नायक सहित कई नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए।

हथियार व गोली के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

चतरा: जिले के सदर थाना क्षेत्र के बिंड मोहल्ला स्थित शहादत चौक में 16 अगस्त को हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए कांड में संलिप्त दो आरोपियों को सोमवार की तड़के सदर थाना क्षेत्र के कुल्लू मोड़ से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी हजारीबाग भागने के फिराक में लगे थे।आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा, दो जिंदा कारतूस, एक चाकू, एक पल्सर मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपियों की पहचान शहादत चौक निवासी मो अकबर उर्फ रौफित तथा मो समीर कुरैशी के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ सदर थाना में पूर्व से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उक्त जानकारी सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी अनिमेष नैथानी ने दी। एसपी ने बताया कि इस घटना में मो शहजाद कुरैशी नामक युवक जखमी हुआ था। मामले को लेकर सदर थाना कांड संख्या 346/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।एसपी ने बताया कि घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। एसपी ने बताया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सन्नी वर्धन के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया था।

सेक्स रैकेट का खुलासा होने के बाद चांदनी होटल सील

चतरा: शहर के न्यू परिसदन भवन के सामने स्थित चांदनी होटल को सोमवार को प्रशासन ने आखिरकार सील कर दिया।दंडाधिकारी की मौजूदगी में होटल के मुख्य गेट और शटर पर ताला लगाकर उसे अगले आदेश तक सील किया गया। होटल सील किए जाने की यह कार्रवाई पुलिस-प्रशासन द्वारा पूर्व में दर्ज की गई प्राथमिकी के बाद की गई है।बताया गया कि 21 अगस्त को पुलिस ने चांदनी होटल में छापेमारी की थी। इस दौरान होटल में कथित रूप से चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ था।पुलिस ने मौके से पांच युवतियों समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया था।सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत (जेल) में भेज दिया गया था।घटना के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से होटल को सील करने के लिए संबंधित प्रशासनिक पदाधिकारियों को पत्र भेजा गया था।इसी पत्र के आधार पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी जहुर आलम ने होटल को सील करने का आदेश जारी किया।होटल को सील करने के लिए दंडाधिकारी के रूप में विशेष प्रमंडल में तैनात सहायक अभियंता आलोक कुमार चौधरी को प्रतिनियुक्त किया गया था। जानकारी के अनुसार होटल को सील करने का आदेश करीब चार दिन पूर्व ही जारी कर दिया गया था, लेकिन सील करने में काफी विलंब हुआ।सोमवार को दंडाधिकारी की मौजूदगी में होटल के मुख्य गेट और शटर पर कुल चार ताले लगाकर उसे सील कर दिया गया।सीलिंग की कार्रवाई के दौरान दंडाधिकारी सहायक अभियंता आलोक कुमार चौधरी, एएसआई रवि रंजन समेत पुलिस बल के जवान मौजूद थे। प्रशासन की ओर से होटल को अगले आदेश तक बंद रखने की कार्रवाई की गई है।

झारखंड

पुलिस एसोसिएशन से विवाद के बीच बोले जयराम

मेरी लड़ाई किसी पुलिसकर्मी से नहीं, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ है, मैं न झुकूंगा न रुकूंगा

संवाददाता

रांची : धनबाद के बरवाअड्डा थाना में दुमरी विधायक जयराम महतो व उनके समर्थकों और बड़ापिछड़ी पंचायत के मुखिया यशोदा देवी के समर्थकों के बीच हुई झड़प के मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यह घटना 21 अगस्त 2026 की रात हो हुई। पुलिस थाना में लगे सीसीटीवी कैमरे व सोशल मीडिया में चल रहे वीडियो व फोटो के माध्यम से नामजद व अज्ञात आरोपियों की पहचान की जा रही है। कुछ लोगों को पुलिस ने नोटिस दिया है, लेकिन अभी तक विधायक जयराम महतो को नोटिस नहीं मिला है।

इधर, जयराम महतो की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस एसोसिएशन का पांच दिनों का अल्टीमेटम 31 अगस्त को समाप्त हो

गया। मंगलवार को पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू मीडिया के सामने विधायक जयराम महतो के माफी नहीं मांगने और गिरफ्तारी नहीं होने के बाद आगे लिये जाने वाले निर्णयों की जानकारी देंगे। वहीं एमपी एमएलए कोर्ट में सरकारी काम में बाधा, लोकसेवक के साथ धक्का-मुक्की व धमकाने के मामले में दुमरी विधायक जयराम महतो की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। सोमवार को धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एमपी एमएलए न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था।

पुलिस एसोसिएशन द्वारा विधायक के खिलाफ मोर्चा खोले जाने के बीच एक सितंबर को जयराम महतो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट



लिखते हुए इसे सरकार की साजिश बताया और कहा कि उन्होंने पुलिसकर्मियों की आवाज को हमेशा उठाने का किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि पुलिसकर्मियों की हर आवाज को केवल मैंने ही सदन में रखने का काम किया है। जब विधानसभा में

नेत्रदान महादान का संदेश लेकर निकला जागरूकता रथ, 8 सितंबर तक चलेगा नेत्रदान पखवाड़ा



संवाददाता

खूंटी : सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में मंगलवार को 41वें नेत्रदान पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉ। ललित रंजन पाठक एवं अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ। रजनी नीलम टोप्पो ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर सिविल सर्जन डॉ। ललित रंजन पाठक ने कहा कि अंधेपन की समस्या के प्रति सभी को गंभीर होने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता सर्वेक्षण के अनुसार कॉर्निया

जनित अंधापन कुल अंधत्व के मामलों में लगभग 7।4 प्रतिशत है तथा इसमें प्रतिवर्ष करीब 20 हजार मामलों की वृद्धि हो रही है, जो चिंताजनक है। उन्होंने सभी स्वास्थ्यकर्मियों को निर्देश दिया कि नेत्रदान के प्रति व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत रिम्स रांची, एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर एवं शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद में नेत्र अधिकोप स्थापित हैं। उन्होंने सामाजिक

संगठनों से भी इस पुनीत पहल में आगे आने की अपील की। साथ ही जिले के इच्छुक लोगों को नेत्रदान के संबंध में जानकारी एवं पंजीकरण के लिए सदर अस्पताल में भ्रमण कर लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक कराया। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला आरसीएच पदाधिकारी डॉ। शोभा किस्पोट्टा, नेत्र सर्जन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक कानन बाला तिकी, जिला लेखा प्रबंधक विकास सिंह, जिला डाटा प्रबंधक श्वेता सिंह, जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉ। उदयन शर्मा सहित सभी नेत्र सहायक एवं स्वास्थ्यकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

संदिग्ध अवस्था में युवक का शव बरामद, हत्या की आशंका

संवाददाता

चतरा : जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के गड़िया गांव में सोमवार की अहले सुबह निमाणांधीन स्वास्थ्य केंद्र के समीप पुल के नीचे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए।मृतक की पहचान गड़िया गांव के 36 वर्षीय विजय यादव के रूप में हुई है।घटना के बाद ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। ग्रामीणों के

अनुसार,सुबह कुछ लोगों की नजर निमाणांधीन स्वास्थ्य केंद्र के पास पुल के नीचे पड़े शव पर गई।। इसके बाद घटना की जानकारी पूरे गांव में फैल गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गयी। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस पहुंची। राजपुर थाना प्रभारी रूपेश कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेजा गया है। साथ ही जांच शुरू कर दी गई है।



होटल में खाया खाना, बिल मांगने पर रॉड और हॉकी स्टिक से हमला

महिला समेत चार घायल

झामुमो कोषाध्यक्ष नितेश अंबानी और युवा अध्यक्ष राहुल यादव समेत अन्य पर मामला दर्ज

दूसरे पक्ष ने भी होटल संचालक और अन्य पर मामला दर्ज करवाया

संवाददाता

चतरा : जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के गांगपुर खेल मैदान के समीप स्थित यादव लाइन होटल फैमिली रेस्टोरेंट में रविवार की देर रात मारपीट की घटना सामने आई। होटल संचालक के अनुसार रात वार्हनों से पहुंचे करीब एक दर्जन लोगों ने खाना खाने के बाद बिल मांगने पर अभद्र व्यवहार करते



हुए रॉड और हॉकी स्टिक से मारपीट की।घटना में होटल संचालक मोहन यादव, चंद्रदेव यादव, उनकी मां सुनीता देवी और पोता मयंक यादव गंभीर रूप से घायल हो गए।घायलों को इलाज के लिए समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गिद्धौर लाया गया।चिकित्सकों ने मनोज यादव व चंद्रदेव यादव के सिर व छाती में गंभीर चोट को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया। घटना

को लेकर सुनीता देवी ने गिद्धौर थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।आवेदन में आरोप लगाया गया है कि रविवार की रात करीब 10-11 बजे झामुमो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राहुल यादव, झामुमो जिला कोषाध्यक्ष नितेश अंबानी, चतरा नगवां निवासी दिलीप यादव, कान्हाचट्टी प्रखंड के गड़िया गांव निवासी मुकेश यादव, झामुमो छात्र मोर्चा जिलाध्यक्ष रूपेश

कुमार यादव, अकौना निवासी सुरेश कुमार समेत करीब एक दर्जन लोग तीन वाहनों से होटल पहुंचे थे। खाना खाने के बाद करीब 4500 रुपये का बिल हुआ। बिल का भुगतान करने के लिए कहने पर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। आवेदन में आगे आरोप लगाया गया है कि इसके बाद हॉकी स्टिक, रॉड व धारदार हथियार से होटल संचालक व उसके



परिजनों के साथ मारपीट की गई। मारपीट में चार लोग घायल हुए। साथ ही होटल के काउंटर से करीब 10 से 15 हजार रुपये लेकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही गिद्धौर पुलिस रात में ही होटल पहुंची और मामले की जानकारी ली। साथ ही थार को जल्द कर थाना लाया। इस संबंध में गिद्धौर थाना प्रभारी पुरुषोत्तम अग्निहोत्रीने कहा कि दोनों ओर

से मारपीट को लेकर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। उन्होंने बताया कि होटल संचालक सुनीता देवी के आवेदन पर कांड संख्या 87/26 एवं दूसरे पक्ष लावालौंग थाना क्षेत्र के राजन पासवान के आवेदन पर कांड संख्या 88/26 दर्ज किया गया है।थाना प्रभारी ने बताया कि अनुसंधान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाई की जाएगी।



उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को ट्रॉफी व मेडल देकर किया गया सम्मानित

संवाददाता

चतरा : जिले के हंटरगंज प्रखंड क्षेत्र के उर्दू स्कूल दन्तार के प्रांगण में सुन्नत गौसिया रजविया मुसाहेबुल उलूम दन्तार के तत्वावधान में शानदार जलसा सह इनामी मुकाबला का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में मदरसा के बच्चों ने नात शरीफ, तकरीर और इस्लामिक शायरी की शानदार प्रस्तुति देकर पूरी महफिल को नूरानी कर दिया। बच्चों की प्रस्तुति ने मौजूद लोगों की खूब वाहवाही बटोरी।कार्यक्रम में हजरत हाफिज व कारी मौलाना जुल्करनैन साहब, हाफिज फिरदौस साहब, हाफिज मो। मुख्तार साहब, हाफिज मो। गुफरान साहब एवं हाफिज मो। सैफ रजा समेत कई उलेमा एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उन्हें शिक्षा के साथ संस्कार और अनुशासन को जीवन में अपनाने का संदेश दिया।वहीं उत्तर प्रदेश से पहुंचे

गुलाम हामिद रजा ने अपने संबोधन में भारत के मुसलमानों के बीच शिक्षा के गिरते स्तर और समाज की बदहाली पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा को तरक्की का सबसे मजबूत माध्यम बताया।उन्होंने बच्चों और अभिभावकों से शिक्षा के प्रति गंभीर होने की अपील की।कार्यक्रम को सफल बनाने में युवा नेता मो। इरफान अंसारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।इनके प्रयासों की कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सराहना की।कार्यक्रम में बतौर प्रमुख अतिथि पहुंचे मो। सज्जाद अंसारी, प्रधानाध्यापक, एवं मो। इरफान अंसारी ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया।सम्मान मिलने पर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। जलसे के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी रही।बच्चों की शानदार प्रस्तुति और शिक्षा को लेकर दिए गए संदेश से ग्रामीणों में भी शिक्षा के प्रति जागरूकता और जुड़ाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आयोजनों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को मंच देने के साथ-साथ उन्हें शिक्षा और संस्कार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।



झारखंड के थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने में देरी पर हाईकोर्ट ने जतायी नाराजगी

संवाददाता

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने पर कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारियों की रुचि यह सुनिश्चित करने में है कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे न लगाए जाएं। 18 जुन 2026 के आदेश और इससे पहले हाईकोर्ट की पीठों द्वारा दिए गए कई निर्देशों के बावजूद थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं।

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार



की ओर से पहले भी टेंडर निकालने और फिर उसे रद्द करने

नहीं हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश का अब तक पालन नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है।

कोर्ट ने वर्तमान तदाशा मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर 2026 को

संवाददाता

रांची : चर्चित कोयला व्यापारी एलबी सिंह की पत्नी को चर्चित कोयला व्यापारी एलबी सिंह की पत्नी को धन संपत्ति व निवेश के बारे में कुछ नहीं पता

पूछताछ शुरू की। यह सिलसिला शाम करीब पांच बजे तक चला।

लेकिन ईडी के हर महत्वपूर्ण सवाल को उन्होंने यह कहते हुए टाल दिया कि उन्हें कुछ मालूम नहीं। निवेश के लिए कैसे कहाँ से आये। पैसे कहाँ-कहाँ निवेश किए गए। निवेश के लिए पैसे का स्रोत क्या है। इस तरह के सभी सवालों के जवाब में आरती सिंह ने कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं। यह तो उनके पति ही जानते होंगे।

दरअसल ईडी द्वारा भेजे गये तीसरे समन के आलोक में आरती सिंह 31 अगस्त को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंची थीं। आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ईडी के अधिकारियों ने उनसे

बार समय भेजने के बाद वह पूछताछ के लिए हाजिर तो हुआ। लेकिन ईडी के अधिकांश सवालों को अभी याद नहीं कहकर टालता रहा। दूसरे दौर की छापेमारी के दौरान प्रीज किये गये 160 पैसे कहाँ से आये। पैसे कहाँ-कहाँ निवेश किए गए। निवेश के लिए पैसे का स्रोत क्या है। इस तरह के सभी सवालों के जवाब में आरती सिंह ने कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं। यह तो उनके पति ही जानते होंगे।

उल्लेखनीय है कि कोयला घोटाले में पहले दौर की छापेमारी के बाद ईडी ने एलबी सिंह को समन किया था। कई बार समय भेजने के बाद वह पूछताछ के लिए हाजिर तो हुआ। लेकिन ईडी के अधिकांश सवालों को अभी याद नहीं कहकर टालता रहा। दूसरे दौर की छापेमारी के दौरान प्रीज किये गये 160 पैसे कहाँ से आये। पैसे कहाँ-कहाँ निवेश किए गए। निवेश के लिए पैसे का स्रोत क्या है। इस तरह के सभी सवालों के जवाब में आरती सिंह ने कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं। यह तो उनके पति ही जानते होंगे।

उल्लेखनीय है कि कोयला घोटाले में पहले दौर की छापेमारी के बाद ईडी ने एलबी सिंह को समन किया था। कई बार समय भेजने के बाद वह पूछताछ के लिए हाजिर तो हुआ। लेकिन ईडी के अधिकांश सवालों को अभी याद नहीं कहकर टालता रहा। दूसरे दौर की छापेमारी के दौरान प्रीज किये गये 160 पैसे कहाँ से आये। पैसे कहाँ-कहाँ निवेश किए गए। निवेश के लिए पैसे का स्रोत क्या है। इस तरह के सभी सवालों के जवाब में आरती सिंह ने कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं। यह तो उनके पति ही जानते होंगे।

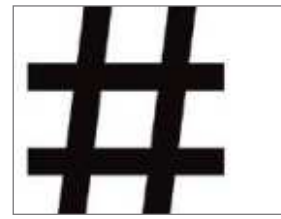
सेवानिवृत्त हुए दक्षिण छोटानागपुर के आयुक्त मनोज कुमार



विनय मिश्रा

भारतीय प्रशासनिक सेवा 2007 बैच के लोकप्रिय,कर्मठ व अपने उत्कृष्ट कार्यों से पहचाने जाने वाले दक्षिण छोटानागपुर के 28वें आयुक्त के रूप में पदस्थापित मनोज कुमार सेवानिवृत्त हो गये। उन्हें रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजोत्री के अलावा अन्य अधिकारी व पदाधिकारियों ने भी ससम्मान विदाई दी और उनके कार्यों को बेहतर, उत्कृष्ट और प्रेरणास्रोत बताया। गौरतलब हो कि आयुक्त श्री कुमार इससे पूर्व कोल्हान प्रमंडल के भी लोकप्रिय आयुक्त रह चुके हैं तथा उत्तरी छोटानागपुर के भी प्रभारी आयुक्त रह चुके हैं। इस प्रकार से राज्य के पांच प्रमंडलों में से तीन प्रमंडलों के आयुक्त रहने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। इसके अलावा श्री कुमार बोकारो के उपायुक्त के अलावा कई महत्वपूर्ण विभागों के सचिव भी रह चुके हैं।

रिफॉर्म मंच के बाद चयनित अभ्यर्थियों ने चलाया हैशटैग अभियान



रांची : जेपीएससी रिफॉर्म मंच ने दो दिन पहले सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक्स पर हैशटैग अभियान चलाया था। इसके बाद जेपीएससी व जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने एक सितंबर को एक हैशटैग अभियान शुरू किया है।

इस हैशटैग पर लोग तरह-तरह से अपनी बातें रख रहे हैं। कोई लिख रहा है कि न्याय मिलना चाहिए जो सही है। तो कोई लिख रहा है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए न कि मेहनत से पास हुए छात्रों को। तो कई एआई से फोटो बनाकर कह रहा है कि सालों की मेहनत, कईयों ने नौकरी छोड़कर सपनों को चुना, हजारों परिवारों की उम्मीदें जुड़ी हैं, इसलिए मेहनती छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। दोषियों को सजा मिले, निर्दोष को न्याय मिले।

दुर्गा पूजा, दीवाली व छठ से पहले बेंगलुरु से झारखंड आने वाली ट्रेनों में सीट नहीं, स्पेशल ट्रेन की मांग तेज

संवाददाता

रांची: दुर्गा पूजा, दीवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहार करीब हैं। ऐसे में बेंगलुरु में रहने वाले झारखंड, बिहार और ओडिशा के लोगों के सामने घर लौटने की परेशानी बढ़ गई है। बेंगलुरु से झारखंड आने वाली कई ट्रेनों में सीटें उपलब्ध नहीं हैं, जबकि कुछ ट्रेनों में वेटिंग काफी लंबी हो गई है। ऐसे में झारखंड रेल यूजर्स एसोसिएशन ने साउथ वेस्टर्न रेलवे के बेंगलुरु डिवीजन के उअट को पत्र भेजकर स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग की है।

दो प्रमुख रूट पर स्पेशल ट्रेन की मांग: एसोसिएशन ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने का सुझाव दिया है। पहले प्रस्ताव में येलहंका से धनबाद के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की गई है। यह ट्रेन डीएमएम, जीएनटी, आरजीडीए, आरएससी और बीकेएससी होते हुए चलाने का सुझाव दिया गया है।

इसके अलावा हुसूर या बेंगलुरु से हटिया के लिए भी ट्रेन चलाने का प्रस्ताव दिया गया है। इन रूटों पर सप्ताह में दो दिन और कुल मिलाकर 32 अप-डाउन ट्रिप चलाने की मांग की गई है। दूसरे प्रस्ताव में येलहंका से टाटानगर और आदित्यपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की गई है। यह ट्रेन जीटीएल,



इसके अलावा हुसूर या बेंगलुरु से हटिया के लिए भी ट्रेन चलाने का प्रस्ताव दिया गया है। इन रूटों पर सप्ताह में दो दिन और कुल मिलाकर 32 अप-डाउन ट्रिप चलाने की मांग की गई है। दूसरे प्रस्ताव में येलहंका से टाटानगर और आदित्यपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की गई है। यह ट्रेन जीटीएल,

वाईजी, सीएचजेड, बीजेडए, बीजेडएम और बीबीएस होते हुए चलाने का सुझाव है। इस रूट पर कुल 16 ट्रिप चलाने का प्रस्ताव दिया गया है। मौजूदा ट्रेनों में सीटों का संकट एसोसिएशन के अनुसार, बेंगलुरु से रांची आने वाली एसएमवीबी हटिया एक्सप्रेस और

रश्मि हटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस में कई श्रेणियों में बुकिंग बंद हो चुकी है। सीट की स्थिति में ग्रीट दिखवाई दे रहा है। 15 अक्टूबर की ट्रेन के पूरी तरह रद्द होने की जानकारी भी दी गई है। बेंगलुरु से टाटानगर जाने वाली ट्रेनों में भी वेटिंग 100 के पार पहुंच गई है। वहीं, बेंगलुरु से बोकारो स्टील सिटी और धनबाद



नहीं करना चाहिए। एसोसिएशन ने मामले को पुलिसकर्मियों के सम्मान से जोड़ते हुए कार्रवाई की मांग की है।

विधायक से 24 घंटे के भीतर माफी मांगने की अपील की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। विधायक के इस रुख के बाद पुलिस एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि यदि मामले

में गिरफ्तारी नहीं होती है तो राज्यभर में आंदोलन किया जाएगा। एसोसिएशन के इस ऐलान से पुलिस महकमे और राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। वहीं, विधायक जयराम महतो का कहना है कि उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़े। उन्होंने एसोसिएशन की मांग

को मानने से इनकार कर दिया है। अब मामला महज बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है। एक ओर पुलिस एसोसिएशन कार्रवाई की मांग पर अड़ा है, वहीं विधायक अपने रुख पर कायम हैं। ऐसे में प्रशासन की अगली कार्रवाई और एसोसिएशन के आंदोलन के फैसले पर सबकी नजर है।

के लिए फिलहाल सीधी ट्रेन उपलब्ध नहीं होने से यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है। एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि हैदराबाद से टाटानगर के लिए सीधी ट्रेन नहीं है और उपलब्ध विकल्पों में भी सीट मिलना मुश्किल है।

समय रहते फैसला लेने की अपील: जेआरयूए के अध्यक्ष कुमार अभिषेक, सचिव नैयर इमाम और कोषाध्यक्ष छोटी कुमारी ने रेलवे से जल्द स्पेशल ट्रेनों की घोषणा करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि त्योहारों के समय बड़ी संख्या में लोग अपने घर लौटते हैं। ऐसे में पर्याप्त ट्रेन नहीं होने पर यात्रियों को महंगे टिकट, लंबी वेटिंग और कई बार दूसरे रास्तों से यात्रा करने की मजबूरी होती है। एसोसिएशन ने रेलवे से मांग की है कि त्योहार शुरू होने से पहले स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर दी जाए, ताकि लोग समय पर टिकट बुक कर सकें और परिवार के साथ त्योहार मना सकें।

अभी तो ये कांग्रेसियों की अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है : विजय शंकर नायक

राहुल गांधी पर फर्जी एफआईआर लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश

मेट्रो रेज

रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रदेश प्रवक्ता विजय शंकर नायक ने हल्द्वानी प्रकरण में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज फर्जी एफआईआर को राजनीतिक प्रतिशोध और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करार देते हुए भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है।



विजय शंकर नायक ने कहा कि राहुल गांधी ने कोई अपराध नहीं किया, उन्होंने उस मानसिकता पर सवाल उठाया है जो आज भी जाति और छुआछूत के नाम पर संविधान की आत्मा को चुनौती देती है। सवाल यह है कि भाजपा को राहुल गांधी की आवाज से इतनी घबराहट क्यों है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, जो स्वयं दलित समाज से आते हैं, की सभा के बाद उसी स्थल के शुद्धिकरण को लेकर गंभीर सवाल उठे। राहुल गांधी ने इसी घटना पर निपक्ष कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन कार्रवाई मांगने वाले राहुल गांधी पर ही एफआईआर कर देना भाजपा की दोहरी राजनीति और सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण है।

नायक ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा को दलित सम्मान की चिंता होती तो पहले खरगे जी के अपमान की जांच कराती, न कि राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज कराती। संविधान के सामने मनुवादी सोच की कोई औकात नहीं है और कांग्रेस सामाजिक न्याय की लड़ाई से पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यदि वास्तव में लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय में विश्वास करती है तो उसे उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगना चाहिए कि राहुल गांधी की शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय उनके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज की गई?

आदिम जाति सेवा मंडल छात्रावास में छात्रों के बीच बांटा गया वस्त्र

मेट्रो रेज

रांची: राजधानी के निवारणपुर स्थित आदिम जाति सेवा मंडल छात्रावास में छात्र-छात्राओं के बीच सेवानिवृत्त बैंक कर्मी अभिजीत भट्टाचार्य व उनकी धर्मपत्नी शुभा भट्टाचार्य ने वस्त्र वितरित किया।

इस अवसर पर श्री भट्टाचार्य ने कहा कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है।

पीढ़ित मानवता की सेवा करने से सुखद अनुभूति होती है। उन्होंने छात्रावास में रह रहे छात्र-छात्राओं को शिक्षा ग्रहण कर एक बेहतर ईसान बनकर समाज के नव निर्माण में सहयोग करने की अपील की। इस मौके पर शहर के जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता तुषार कांति शेट सहित अन्य मौजूद थे।



उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग (विधि शाखा)

झापांक 1901/विधि, दिनांक 10.08.2026
Mutation Revision No. 106/2024
Tarun Kumar Besra -Versus- State & Ors

नोटिस बनाम—

1. Tarun Kumar Besra
S/o Late Ajay Besra R/o Village- Hurburu
P.S.- Korrah, Dist.- Hazaribag.
बजरिये इस नोटिस के माध्यम आपको सूचित किया जाता है कि उपायुक्त न्यायालय, हजारीबाग में आपके द्वारा दाखिल वाद संख्या 106/2024 Tarun Kumar Besra -Versus- State & Ors में विगत कई तिथियों से आप लगातार अनुपस्थित हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वाद के निष्पादन में आपको कोई अभिरुची नहीं है।
अतः न्यायालय के आदेश के क्रम में वाद में अगली निर्धारित तिथि 08.09.2026 को सभी साक्ष्य एवं कागजात के साथ 11:00 बजे पूर्णतः उपायुक्त महोदय के न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से निश्चित रूप से उपस्थित होकर पक्ष रखने हेतु आपको अंतिम अवसर दिया गया है, अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में वाद की कार्यवाई खारिज कर दी जायगी।
नोटिस न्यायालय के मुहर से जारी किया गया।
PR 388718 (Law)26-27"D

प्रभारी पदाधिकारी,
विधि शाखा, हजारीबाग



सूक्ति

सबसे प्रेम करो, कुछ पर विश्वास करो
अन्याय किसी के साथ मत करो : शेक्सपियर

भागवत का डीएनए संदेश

सरसंघचालक मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क (अमेरिका) में जो संबोधन दिया है, वह उनकी सोच की पुनरावृति ही है, लेकिन संदेश अमेरिकी जमीन से दिया गया है, लिहाजा उसकी गुंज वैश्विक है। मुस्लिम धर्मगुरुओं, अमेरिकी विचारकों और खुली सोच के समर्थकों ने संबोधन की सराहना की है। उसे स्वागतयोग्य भी माना है, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी करार दिया है। आरएसएस अपनी स्थापना के 100 साल मना रहा है, लिहाजा सरसंघचालक अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन के प्रवास पर हैं। बहरहाल भारत में जो जमात संघ-विरोध की राजनीति करती रही है, हर बुराई और विवाद के लिए संघ को ही आरोपित करती रही है, वह पुराने पन्ने खोल कर सरसंघचालक के विरोधाभासों, कथनी-करनी में अंतर, उनके विचारों के उनके अपने ही घर में उल्लंघन सरीखी तोहमते लगा रहे हैं। संबोधन को संघ-प्रमुख का वैचारिक योगलापन करार दे रहे हैं। यह सामान्य प्रवृत्ति है। उन्हें ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी देश के संविधान ने दी है। दरअसल सरसंघचालक मोहन भागवत के अमेरिकी संबोधन का सारांश यह है कि हिंदू-मुसलमान का डीएनए एक ही है। एकता और विविधता ही हमारा डीएनए है। यदि कोई हिंदू सोचता है कि देश में मुसलमान नहीं होने चाहिए, तो वह हिंदू नहीं रह जाएगा। हिंदुत्व का अर्थ मुसलमान को देश के बाहर करना नहीं है। यही भागवत के हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। विविधता में एकता ही हमारा राष्ट्रवाद है, सांस्कृतिक एकात्मवाद है। धर्म का लक्ष्य सत्य की ओर ले जाना है। सभी रास्ते एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं। धर्म अनेक हैं, लेकिन सत्य एक ही है। इन्सानियत सबसे मूल्यवान है। सरसंघचालक ने ऐसा संबोधन पहली बार नहीं दिया है। विदेशी जमीन पर यह प्रथम संबोधन हो सकता है! अलबत्ता मोहन भागवत 2018 से यही संदेश लगातार देते रहे हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बयान भी दिया था कि हरेक मस्जिद के नीचे शिवालय दूढ़ना बंद करें। उसका जबाबदस्त असर हुआ और ऐसी सांप्रदायिक कवायदे बहुत कम हो गईं। काशी, मथुरा संघ परिवार और भाजपा के सनातन मुद्दे हैं और कहा जाता रहा है कि अदालत का जो फैसला होगा, वह मान्य होगा। दरअसल सरसंघचालक भागवत अपनी सोच और वैचारिकता में बिल्कुल स्पष्ट हैं, लिहाजा वह हिंदू-मुस्लिम के एकत्व वाले राष्ट्र की कल्पना करते रहे हैं, लेकिन अहम सवाल यह है कि संघ-प्रमुख किन्हें संबोधित करते रहे हैं? संघ के प्रचारक रहे और अब देश के प्रधानमंत्री मोदी खुद कपड़ों से पहचानने , दाढ़ी-टोपी वाले , ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और आपका मंगल-सूत्र छीनने वाले आदि सार्वजनिक टिप्पणियां कर मुसलमानों पर आघात करते रहे हैं। भाजपा में एक बड़ी जमात है, जो सार्वजनिक रूप से मुस्लिम-विरोधी है, कट्टर विरोधी है। कांवड़-यात्रा निकलती है, तो मुसलमानों को पहचान छिपानी पड़ती है। उनकी दुकानों, रेहड़ियों और उनके ढाबों पर अनावश्यक, अनधिकृत जांच के छापे मारे जाते हैं। सर्वोच्च अदालत तक इनके खिलाफ फैसला सुना चुकी है। देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का अभियान असम से चलाया गया, लेकिन प्राथमिक जांच में ही हिंदू या बंगाली हिंद बहुसंख्यक पाए गए। अभियान पर ढक्कन लगा दिया गया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अब भी एनआरसी के अभियान पर आमादा हैं। हालांकि संघ-प्रमुख के संबोधन के बाद खासकर भाजपा में गहरी खामोशी है, अलबत्ता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद निशिकांत दुबे जैसों की भरपूर जमात है, जो बात-बात पर, औसत मुद्दों और विवाद पर, मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाने की धमकी देते रहे हैं। जिन्हें पाकिस्तान जाना था, वे चले गए, 80 लंबे साल भी बीत गए, पीढ़ियां बदल गईं, अब मुसलमान भी भारतीय हैं। हिंदू-मुसलमान की नारेबाजी, नफरत, जारी रहेगी, तो देश में एकता, एकत्व का डीएनए अथवा सांस्कृतिक एकात्मवाद की स्थितियां कैसे संभव होंगी? विरोधी भी अपनी पूर्वाग्रही मानसिकता बदलें। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का आरएसएस से कोई संबंध नहीं था। कांग्रेस, सपा के कथित प्रवक्ता टीवी बहसों में हररोज यह आरोप चिल्लाते रहते हैं। द्वितीय सरसंघचालक गुरु गोलावलकर की किताब बंच ऑथेंट्स फरवरी, 1966 में छपी थी। वह किताब देश का संविधान या पवित्र धर्म-ग्रंथ नहीं है। गुरु जी के भाषणों, आलेखों, निबंधों, संवादों का संकलन है। हमारा दावा है कि विरोधियों ने यह किताब पूरी तरह पढ़ी भी नहीं होगी। यह आज प्रासंगिक भी नहीं है। उसका लगातार, हररोज जिन्न होता रहेगा, तो फासले और भी गहरे होंगे।

आरक्षण हक नहीं, व्यवस्था है

भारत में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह राजनीति और चुनाव का अमोघ अस्त्र बन चुका है। संविधान में भी अनुच्छेद 340, 341 में उल्लेख है कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विषमताओं, विसंगतियों को खत्म करने और कुछ समुदायों को समानता की मुख्धधारा में लाने को आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। यह व्यवस्था आजादी और संविधान लागू होने के बाद सिर्फ 10 सालों के लिए थी, लेकिन 79 साल की आजादी के बाद भी जारी है और उसे निरंतर जारी रखना सरकारों की जिवांशता भी है। आरक्षण संवैधानिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार भी नहीं है, सिर्फ एक व्यवस्था है, जिसे बढ़ाया जाता रहा है। अनुच्छेद 15 और 16 में आरक्षण की शर्िक राख्य को दी गई है, लेकिन सर्वोच्च अदालत यह भी स्पष्ट कर चुकी है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक व्यवस्था है। संविधान में आर्थिक रूप से गरीब, कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। क्या ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, भूमिहार आदि सवर्ण वर्ग गरीब नहीं हैं? हमारे पुरखों ने यह कल्पना क्यों नहीं की? क्या उस समय देश में कोई भी सवर्ण कमजोर नहीं था? ये सवाल निरंतर अनुत्तरित रहेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10 फीसदी का आरक्षण संसद से पारित कराया था, जिसे सर्वोच्च अदालत ने भी न्यायिक माना, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। दरअसल छिद्र और विसंगतियां आरक्षण की व्यवस्था में हैं। उस संदर्भ में सर्वोच्च अदालत ने क्रीमी लेयर का फैसला सुनाया था। क्रीमी लेयर की आय-सीमा 8 लाख रुपए सालाना तय है। उससे अधिक आय वाले आरक्षित वर्गों के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन यह न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं है। हम ऐसे कई परिवारों को जानते हैं, जिनमें पीढ़ी-दर-पीढ़ी आईएसएस, आईपीएस अधिकारी हैं। उनके परिवारों को आरक्षण क्यों चाहिए? या क्यों दिया जाना चाहिए? लोकसभा में 131 सांसद आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के 84 और जनजाति के 47 सांसद हैं। राज्यों की विधानसभाओं में भी सैकड़ों आरक्षित विधायक हैं। मंत्री, राज्यमंत्री और अन्य पदों पर भी आरक्षित चेहरे हैं। यदि राष्ट्रीय स्तर के चेहरों का उल्लेख करें, तो बसपा प्रमुख एवं उप्र की चार बार मुख्यमंत्री रहें मायावती, लोकसभा सांसद प्रमोद एंज के ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और रामदास अठावले आदि के परिवारों और बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? पासवान परिवार में रामविलास पासवान (अब दिवंगत) के समय से भाई, भतीजा, दामाद सभी सत्ता में रहे अथवा सांसद-विधायक रहे। अखिर सामाजिक पिछड़ेपन, विषमताओं से उबरने का मापदंड क्या है?

महंगाई नियंत्रण की कारगर रणनीति जरूरी

प्याज, टमाटर और आलू की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए नाफेड जैसे सरकारी संगठनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर सीधी बिक्री बढ़ाई जानी होगी। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए व्यापारियों के स्टॉक सीमाओं की सख्त निगरानी आवश्यक होगी ।

जयंती लाल भंडारी

इन दिनों महंगाई पर प्रकाशित हो रही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में भारत में महंगाई बढ़ने से आम आदमी के जीवन की मुश्किलें बढ़ने संबंधी चिंताएं प्रस्तुत की जा रही हैं। हाल ही में 27 अगस्त को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एस एंड पी ग्लोबल ने मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण ऊंची ऊर्जा कीमतों और अल नीनो से प्रभावित कमजोर मानसून की चुनौतियों की वजह से चालू वित्त वर्ष 2026-27 में भारत में खुदरा महंगाई (सीपीआई) के बढ़कर 5.1 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान जताया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति सहित प्रमुख आर्थिक एजेंसियों ने भारत में खुदरा महंगाई बढ़ने की चेतावनी दी है। एचडीएफसी बैंक ने सितंबर से खुदरा महंगाई दर लगातार 5 प्रतिशत से ऊपर रहने का अनुमान लगाया है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स व जेपी मॉर्गन ने खाद्य और कच्चे तेल की बढ़ती लागत के कारण महंगाई में और वृद्धि की चिंता जाहिर की है। एसबीआई इकोविप रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जो खुदरा महंगाई अगस्त में 4.7 प्रतिशत अनुमानित है, वह अक्टूबर-नवंबर में 6 प्रतिशत के पार पहुंच सकती है। ऐसे में सरकार के द्वारा महंगाई नियंत्रण के और अधिक कारगर रणनीतिक कदम जरूरी दिखाई दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2026 में भारतीय बाजार में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया गया है। मौसम की अनिश्चितता और फसल प्रभावित होने से चीनी के खुदरा भाव ऊंचाई पर पहुंच गए हैं।

सीमित आपूर्ति के कारण प्याज के दाम पिछले साल की तुलना में तेजी से बढ़े हैं। इसके अलावा सरसों तेल, रिफाईंड तेल और दालों के दाम भी ऊंचे स्तर पर बने

हुए हैं। त्योहारों के मौसम में मांग बढ़े, चारे की लागत और परिवहन खर्च में वृद्धि के कारण दूध, मिठाइयों, पैकबंद खाद्य पदार्थों और पैकड चाय की कीमतों में और बढ़ोतरी होने की आशंका जताई जा रही है। यह परिदृश्य स्पष्ट संकेत देता है कि कमजोर मानसूनऔर आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमते आने वाले महीनों में आम नागरिक के बजट पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में जुलाई महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.45 प्रतिशत हो गई है, जो जून में 4.38 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 4 प्रतिशत के तय लक्ष्य से ऊपर बना हुआ है। महंगाई में इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें हैं। निश्चित रूप से खाद्य वस्तुओं की बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी की थाली महंगी हो गई है। जीवन निर्वाह लागत बढ़ गई है। क्रिसलिस की अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2026 में घर पर बनने वाली शाकाहारी थाली की औसत लागत सालाना आधार पर 4 प्रतिशत बढ़कर 29.1 रुपए हो गई। यह पिछले 7 महीनों का उच्चतम स्तर है। वहीं, मांसाहारी थाली की कीमत 9 प्रतिशत बढ़कर 58.3 रुपए पर पहुंच गई। थाली महंगी होने का मुख्य कारण प्याज, खाद्य तेल और रसोई गैस की दरों में वृद्धि है। इस परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद देश में महंगाई, आर्थिक स्थिति और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि से जुड़ी तस्वीर पेश करते हुए कहा कि वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल और कमजोर मानसून की चुनौतियों के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी

हुई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.0 प्रतिशत कर दिया है। जहां खाद्य वस्तुओं के क्षेत्र में महंगाई में कुछ वृद्धि के संकेत हैं, वहीं अन्य क्षेत्रों में महंगाई बढ़ने के संकेत नहीं हैं। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में मानसून, अल नीनो और पश्चिम एशिया के संघर्ष की वजह से खाने-पीने की वस्तुएं और ईंधन महंगे हो सकते हैं। निःसंदेह अब ऊंची ऊर्जा लागत, अल नीनो और कमजोर मानसून के कारण महंगाई की चिंता बढ़ती जा रही है।

इससे कृषि पर मंडराता खतरा भी दिखाई दे रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जून-सितंबर के बीच देश में सामान्य वर्षा के मुकाबले लगभग 15 प्रतिशत की कमी अनुमानित की गई है। इस स्थिति के पीछे अल-नीनो प्रभाव को मुख्य कारण माना जा रहा है, जिसने मानसून की गति को धीमा कर दिया है। शुरूआत में कम बारिश और मिट्टी में नमी की कमी के कारण इस वर्ष खरीफ फसलों की बुआई का कुल रकबा प्रभावित हुआ है। विशेष रूप से धान, सोयाबीन और दलहन जैसी फसलों का बुआई क्षेत्र पिछले साल की तुलना में सिकुड़ गया है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं हैं, वहां फसलों के सूखने का जोखिम काफी बढ़ गया है। बारिश की लगातार कमी से मिट्टी में नमी का स्तर घट रहा है। इससे न केवल कुल खाद्यान्न उत्पादन घट सकता है, बल्कि किसानों की आय प्रभावित होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल दबाव पड़ सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा जुलाई की शुरूआत से लेकर अब तक महंगाई नियंत्रण के लिए बहुआयामी रणनीतिक कदमों के साथ आगे बढ़ेगी। सरकारी गोदामों से गेहूं, चावल और दालों को उपयुक्त रूप से खुले बाजार में जारी किया जाना होगा, ताकि आगामी त्योहारी सीजन में आपूर्ति बनी रहे। प्याज, टमाटर और आलू की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए नाफेड जैसे सरकारी संगठनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर सीधी बिक्री बढ़ाई जानी होगी।

स्कूल सुधारने का अभियान और विकास

सीजेपी की मांग पर शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा तक देना पड़ा। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने सरकारों को देश की असली सच्चाई से सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। वरना इससे पहले तो लग ही नहीं रहा था कि देश की परीक्षा प्रणाली और स्कूलों तथा शिक्षा की नरक होती हालत भी कोई मुद्दा हो सकता है। देश की सरकारों के लिए यह कोई बड़ा मुद्दा था ही नहीं, इसे नई पीढ़ी के युवाओं ने जबरन सरकार के गले में डाल कर यह एहसास कराया कि यह बड़ा मुद्दा है। अभी सिर्फ परीक्षा, स्कूल, शिक्षा ही मुद्दा नहीं हैं। देश में समस्याओं की भरमार है। सडक, बिजली, पानी, रोजगार, स्कूल, कॉलेज, अस्तपताल और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे मौजूद हैं। बस जरूरत इन मसलों पर सडकों पर उतरने की है, सरकारें भी सडक पर आ जाएंगी। अब आंदोलनों के जरिए ही जनता की मांगें मनवाई जासकती हैं।

योगेन्द्र योगी

अब वह दौर आ गया है कि वोट देने के साथ ही देश की समस्याओं को लेकर सरकारों की नींद खोलनी के लिए आम लोगों को सडकों पर उतरना पड़ेगा। संचला बल का इसमें ज्यादा महत्व नहीं है। मुट्ठी भर लोग भी ताकतवर सरकारों से जनहित में अपनी बात मानवा सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और उनके समर्थक जेन-जी के युवाओं ने देश भर में स्कूलों की दयनीय हालत का मुद्दा उठा कर यह साबित कर दिया कि चंद संघर्षशील नौजवान सरकारों का ध्यान आकर्षित करने और समस्या का समाधान करने में कुछ हद तक कामयाब हो सकते हैं। सीजेपी ने देश भर में स्कूलों की खराब हालत को सुधारने के लिए अभियान चलााने की घोषणा की थी। इसी के तहत सीजेपी समर्थक जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव के एक सरकारी स्कूल की हालत जानने के लिए पहुंचे।

यह स्कूल भैंसों के बाड़े में टीन शेड के नीचे चल रहा था। हालांकि सीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को स्थानीय भाजपा विधायक के समर्थकों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उनके साथ हाथपाई की गई। उनकी गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए गए। इसके बावजूद सीजेपी स्कूल की हालत मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए देश को बताने में कामयाब हो गई। इस स्कूल को एक बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। इसका भवन बनाने की घोषणा की गई। चंद सीजेपी कार्यकर्ता तमाम दुश्विारियों के बावजूद स्कूलों के मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में कामयाब हो गए। जयपुर के स्कूलों की हालत के बाद देश भर में सोशल मीडिया पर जर्जर स्कूलों की बहल आ गई। राज्यों की सरकारें विकास की पोल खुलने से बैचैन हो गईं। सोशल मीडिया पर स्कूलों की हालत को लेकर सरकारों की जम कर खिंचाई की गई। स्कूलों की हालत सामने आने के बाद राज्यों में विकास और तरक्की की असलियत उजागर हो गई। सरकारों को फजीहत के बाद

स्कूलों की सुध लेने की घोषणा करने पर मजबूर होना पड़ गया। जयपुर के स्कूल की दुर्दशा का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर गूँजने के बाद राजस्थान की भजन लाल सरकार ने स्कूलों की सुध ली। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने प्रदेश में 3587 नई स्कूल बिल्डिंग और 83783 नए कक्षासरूम बनाए जाने की घोषणा की। राजस्थान के 22589 विद्यालयों में व्यापक निर्माण कर बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाएगा।

वहीं, स्कूलों में जरूरी सुविधाओं के विस्तार के लिए 13616 नए शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। सरकारी विद्यालयों के कायाकल्प के लिए करीब 12500 करोड़ रुपए के बजट से आधारभूत सुविधाएं विकसित करने की योजना है। फिलहाल स्कूलों से जुड़े करीब 3006 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रक्रिया में हैं। सीजेपी के स्कूल सुधारो अभियान के बाद ही उत्तर प्रदेश में सरकार ने 3126 परिषदीय व उच्च प्राथमिक स्कूलों का पुनर्निर्माण व मरम्मत 604 करोड़ रुपए से कराए जाने की घोषणा की। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए 302 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी। इसमें खराब व जर्जर हो चुके भवनों की जगह नई बिल्डिंग का निर्माण कराया जाएगा। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय पर 15.36 लाख रुपए खर्च होंगे। 12243 परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की मरम्मत पर कुल 344.52 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

इसकी पहली किस्त के रूप में 172.26 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। शासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक 72 विद्यालयों में जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण, मरम्मत व अवस्थापना सुविधाओं के लिए विभाग की ओर से 9.62 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। इसी तरह झारखंड और बिहार में पेपर लीक व धांधली के मामलों के बाद युवाओं के धरने-प्रदर्शन के बाद दोनों राज्यों की सरकारों को परीक्षाएं निरस्त करने पर विवश होना पड़ गया। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने छात्र आंदोलनों के बाद जेपीएससी और जेएसएससी की कई परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया। सरकार ने अनिव्यमितताओं और पेपर लीक

की शिकायतों के बाद कुल 22 से अधिक परीक्षाओं को रद्द किया है तथा अन्य पर जांच बिठाई है। बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार ने 4500 पदों के लिए हुई सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की ऑनलाइन परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द कर दिया गया। इससे पहले केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक को रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम 2026 लागू किया।

इसमें परीक्षा में व्यक्तिगत रूप से नकल करने या गलत तरीके अपनाने पर 5 से 10 वर्ष तक की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुमाने का प्रावधान किया गया है। संगठित रूप से पेपर लीक कराने या धांधली करने वाले गिरोहों के लिए 7 से 10 वर्ष की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुमाने का प्रावधान है। परीक्षा आयोजित करने वाली लापरवाह या दोषी एजेंसियों पर 5 करोड़ रुपए तक का जुमाना और परीक्षा कराने पर 8 वर्ष तक की रोक लग सकती है। मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें बनाए जाने की घोषणा की गई।

सीजेपी की मांग पर शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा तक देना पड़ा। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने सरकारों को देश की असली सच्चाई से सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। वरना इससे पहले तो लग ही नहीं रहा था कि देश की परीक्षा प्रणाली और स्कूलों तथा शिक्षा की नरक होती हालत भी कोई मुद्दा हो सकता है। देश की सरकारों के लिए यह कोई बड़ा मुद्दा था ही नहीं, इसे नई पीढ़ी के युवाओं ने जबरन सरकार के गले में डाल कर यह एहसास कराया कि यह बड़ा मुद्दा है। अभी सिर्फ परीक्षा, स्कूल, शिक्षा ही मुद्दा नहीं हैं। देश में समस्याओं की भरमार है। सडक, बिजली, पानी, रोजगार, स्कूल, कॉलेज, अस्तपताल और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे मौजूद हैं। बस जरूरत इन मसलों पर सडकों पर उतरने की है, सरकारें भी सडक पर आ जाएंगी। अब आंदोलनों के जरिए ही जनता की मांगें मनवाई जा सकती हैं।

आपके पत्र

बीमारियों का बड़ा कारण पौष्टिक आहार से दूरी

एक सितंबर से सात सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। आम लोगों को खानपान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मार्च 1975 में एडीए (अमेरिकन डायैटेटिक एसोसिएशन, अब न्यूट्रिशन और डाइट साइंस अकेडमी) ने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाने की शुरूआत की थी। हमारे देश में इसकी शुरूआत वर्ष 1982 में हुई थी। अब हर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर वर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। हम खाने को जो मर्जी खा लें, लेकिन जो खाना हमारे शरीर के लिए उपयोगी न हो या तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन करने के बावजूद हमें कोई न कोई छोटी बड़ी बीमारी परेशान करती रहती है, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम जो कुछ खा रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए उचित नहीं है।

प्रियंका सेठ,रांची

मेट्रो रेज की ओर से स्वताधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक जीतेन्द्र कुमार सिंह के लिए जेके न्यूज नेटवर्क, पिपरटोली, अरगोडा, रांची 834002 (झारखंड) से प्रकाशित तथा शिवासाई पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नियर टेंडर बागीचा, पेट्रोल पंप रा्टी रोड, रांची , (झारखंड) से मुद्रित।

प्रधान संपादक : जीतेन्द्र कुमार सिंह, संपादक : लाल दिवाकर नाथ शाहदेव*, *पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार। समस्त दिवानी विवादों, न्यायोचित कार्रवायों एवं दंडित परिवारों के लिए क्षेत्राधिकार रांची न्यायालय में रहेगा। फोन : 73699017908, R.N.I. No.-JHAHIN/2017/75028 **website : **www.metrorays.in****

email : metrorays.ranchi@gmail.com

जागृति योजना के तहत सशक्त युवा सशक्त भारत अभियान पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित



साहिबगंज : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निदेशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज श्री अखिल कुमार के मार्गदर्शन में जिले में ह्यजागृति योजना, 2025ह्क के तहत ह्यसशक्त युवा, सशक्त भारतह्क अभियान के अंतर्गत व्यापक विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है।इसी क्रम में आज 31 अगस्त 2026 को पैरा लीगल वॉलंटियर्स -न्याय मित्र विकास कुमार, मुस्ताक अंसारी व अन्य द्वारा पतना प्रखंड अंतर्गत अर्जुनपुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया।कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को मौलिक अधिकार, किशोर न्याय व्यवस्था, कानून के उल्लंघन की स्थिति में किशोरों के अधिकार तथा पहली बार अपराध करने वाले युवाओं के पुनर्वास एवं समाज की मुख्यधारा में वापसी से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।वर्तमान डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए विद्यार्थियों को साइबर अपराध, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, एआई आधारित धोखाधड़ी, डीपफेक एवं अन्य डिजिटल अपराधों से बचाव के व्यावहारिक उपाय भी बताए गए। साथ ही विद्यालयों में रैगिंग विरोधी कानून एवं नालसा स्टूडेंट अवेयरनेस रिसोर्स ऑन रैगिंग, 2026 के संबंध में भी जानकारी दी गई।जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव श्री आलोक मरांडी ने बताया कि जिले के विभिन्न विद्यालयों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। पीएलवी-न्याय मित्रों के माध्यम से विधिक जागरूकता का संदेश सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जा रहा है।अभियान का उद्देश्य युवाओं को केवल कानून की जानकारी देना नहीं, बल्कि उन्हें जिम्मेदार, जागरूक एवं सशक्त नागरिक बनाना है, ताकि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हुए समाज एवं राष्ट्र के विकास में प्रभावी भूमिका निभा सकें।

जिला के असर्वेक्षित भूमि में किसानों को बीमा योजना का लाभ मिले : गणेश



साहिबगंज : कृषि बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्ति के बाद भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य गणेश प्रसाद तिवारी सोमवार को दिल्ली में आयोजित प्रथम बोर्ड बैठक में शामिल हुए।जहां उन्होंने अध्यक्ष का स्वागत बुके देकर किया।वही उन्होंने बोर्ड बैठक में कहा कि जिला में किसानों की भूमि असर्वेक्षित है, जिससे किसानों को बीमा का लाभ अभी नहीं मिल रहा है,पूर्व में दिया गया है।अब सर्वे का कागजात खोजा जा रहा है।असर्वेक्षित भूमि धारकों को भी बीमा योजना का लाभ मिले ऐसा पॉलिसी बनाए।वही जिन किसानों को अब तक बीमा नहीं मिला है उसको जल्द से जल्द बीमा योजना का लाभ दिया जाए।बोर्ड बैठक के दौरान कंपनी के कार्यो, नीतियों एवं किसानों के हित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।वही जिला सहित प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा,कृषि बीमा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा ग्रामीण भारत के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसानों को बीमा में आ रही समस्याओं और बीमा का लाभ दिलाने के लिए बैठक में कई मुद्दे रखे। जल्द ही समस्याओं को पूरा करने की बात कही।

साहिबगंज कॉलेज में नवनियुक्त प्राचार्य डॉ.रणजीत कुमार सिंह का भव्य स्वागत



साहिबगंज : साहिबगंज महाविद्यालय के रमन विज्ञान भवन में भूगोल विभाग की ओर से नवनियुक्त प्राचार्य डॉ.रणजीत कुमार सिंह के स्वागत एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया।विभागाध्यक्ष डॉ.मोहम्मद हसनैन ने अंगवस्त्र व पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया।इस दौरान डॉ.हसनैन ने प्राचार्य की शैक्षणिक एवं सामाजिक उपलब्धियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया।अपने संबोधन में डॉ.रणजीत कुमार सिंह ने कहा कि भूगोल सदैव उनका प्रिय विषय रहा है और वे इसी महाविद्यालय में पूर्व में भूगोल विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं।कार्यक्रम में नेपाल में आई बाढ़ की विभीषिका पर विशेष व्याख्यान हुआ।डॉ.हसनैन एवं डॉ.सिंह ने हिमालयी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों बाढ़ के संभावित कारणों और इसके निचले क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की।उन्होंने विद्यार्थियों से प्राकृतिक घटनाओं पर्यावरणीय बदलाव और जलवायु परिवर्तन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने तथा प्रकृति के प्रति जिज्ञासु एवं संवेदनशील बने रहने का आह्वान किया।कार्यक्रम में रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ.अनिल कुमार,भूगोल विभाग के शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

झारखंड

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति को लेकर दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

संवाददाता

साहिबगंज : पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला स्तरीय स्ट्रेयिंग-सह-मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के विभिन्न घटकों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।बैठक के दौरान विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जुलाई 2026 में पीएम पोषण योजना से आच्छादित विद्यालयों में बच्चों की औसत उपस्थिति 69.59 प्रतिशत रही जबकि जून 2026 में यह 68.52 प्रतिशत थी। इस प्रकार जुलाई माह में बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि दर्ज की गई। राज्य स्तर पर जिले की स्थिति 22वें स्थान पर रही। बैठक में विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए आवश्यक एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। नामांकन की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि मार्च 2026 में बाल वाटिका, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल 2,14,366 बच्चों का नामांकन था, जो जुलाई 2026 में घटकर 2,08,290 रह गया। इस प्रकार कुल 6,076 बच्चों के नामांकन में कमी पाई गई। बैठक में



नामांकन में कमी के कारणों की समीक्षा करते हुए विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने तथा शत-प्रतिशत बच्चों को विद्यालय से जोड़ने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जुलाई 2026 में कुल 2,08,290 नामांकित बच्चों में से 50,231 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जो कुल नामांकित बच्चों का 24.12 प्रतिशत है। बैठक में शेष बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण निर्धारित समय-सीमा के भीतर कराते हुए मार्च 2027 तक शत-

प्रतिशत स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।इसी क्रम में आईएफए गोली सेवन की समीक्षा में बताया गया कि जुलाई 2026 में कुल नामांकित 2,08,290 बच्चों में से 1,36,896 बच्चों द्वारा आईएफए गोली का सेवन किया गया, जो 65.72 प्रतिशत है। कम उपलब्धि वाले प्रखंडों में विशेष अभियान चलाकर बच्चों को नियमित रूप से आईएफए गोली का सेवन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।बैठक में बच्चों के आधार की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिले में कुल 2,08,290 नामांकित बच्चों में से

2,00,507 बच्चों के आधार उपलब्ध हैं, जो 96.31 प्रतिशत है। वहीं 1,69,112 बच्चों का आधार प्रमाणीकरण किया जा चुका है, जो 81.23 प्रतिशत है। कम आधार प्रमाणीकरण वाले क्षेत्रों में विशेष ध्यान देते हुए शत-प्रतिशत आधार प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

विद्यालयों में पोषण वाटिका की स्थिति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जिले के कुल 1,280 विद्यालयों में से 1,234 विद्यालयों में पोषण वाटिका संचालित है जो 96.40 प्रतिशत है। शेष 46 विद्यालयों

में भी पोषण वाटिका स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।बैठक में पुनः खोले गए 28 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन पकाने एवं परोसने हेतु आवश्यक बर्तन की उपलब्धता के संबंध में भी समीक्षा की गई। साथ ही विद्यालयों में बच्चों को भोजन ग्रहण करने के दौरान सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैठने हेतु पट्टियां

आसन की व्यवस्था अथवा अन्य उपलब्ध मर्दों से किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा की गई।समिति द्वारा पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के सभी घटकों की नियमित व प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। बैठक में बच्चों की उपस्थिति एवं नामांकन में वृद्धि, स्वास्थ्य जांच, आईएफए गोली सेवन, आधार प्रमाणीकरण, पोषण वाटिका के निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत प्राप्त करने की दिशा में समन्वित एवं परिणामोन्मुखी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।बैठक में उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा, परियोजना निदेशक आईटीडीए श्री संजय कुमार दास, सिविल सर्जन डॉ. रामदेव पासवान, जिला शिक्षा पदाधिकारी नयन कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक श्रीमती उर्मिला हांसदा समेत संबंधित विभागों के पदाधिकारी व समिति के सदस्य उपस्थित थे।

पेड़-पौधे हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं : अमित



संवाददाता

साहिबगंज : गंगा मिशन कोलकाता साहिबगंज की ओर से पर्यावरण संरक्षण हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार वृक्षारोपण और पौधा वितरण अभियान चलाया जा रहा है।इसी अभियान के तहत मंगलवार की सुबह भारतीय रोड स्थित बाबूलाल नंदलाल बोहरा ट्रस्ट परिसर में सरस्वती शिशु मंदिर

साहिबगंज के छात्र-छात्राओं के बीच फलदार पौधों का वितरण किया गया।कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना और उन्हें अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना रहा।इस दौरान स्कूली बच्चों को आम कटहल नारियल सहित विभिन्न फलदार पौधे वितरित किए गए।बच्चों ने भी पौधों को

सुरक्षित रखने और उनका उचित देखभाल करने का संकल्प लिया।इस अवसर पर गायत्री परिवार के कल्याण श्रीवास्तव,गंगा आरती से जुड़े प्रमोद पांडे, चंपक दत्त,रतन अग्रवाल सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षक अमित कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कल्याण श्रीवास्तव ने कहा कि एक पेड़ दस पुत्रों के समान होता

है। उन्होंने कहा कि पेड़-पौधे हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।वृक्ष प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के साथ-साथ हमें फल,छाया और स्वच्छ वातावरण प्रदान करते हैं।उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने आपसा अधिक से अधिक पौधे लगाएं और लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल भी करें।गंगा मिशन के सदस्यों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल किसी एक व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी नहीं है।बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक को इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। विद्यार्थियों के माध्यम से घर-घर तक हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।कार्यक्रम के दौरान बच्चों में पौधों को लेकर उत्साह देखने को मिला।आयोजकों ने भविष्य में भी इस तरह के पौधा वितरण व वृक्षारोपण कार्यक्रम को जारी रखने की बात कही।

सभी बच्चों को पर्यावरण रक्षा का संकल्प दिलाया

संवाददाता

साहिबगंज : गंगा मिशन कोलकाता साहिबगंज की ओर से वृक्षारोपण को लेकर फलदार वृक्षों के पौधा वितरण का कार्य चल रहा है।इसी के तहत 31 अगस्त सोमवार की दोपहर स्थानीय सागमल पथ स्थित टेकनो कनवेंशन पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं के बीच फलदार वृक्ष आम,कटहल,



नारियल,आंवला के पौधा का वितरण किया गया।वितरण स्थानीय भरतिया रोड स्थित बाबूलाल

नंदलाल बोहरा ट्रस्ट परिसर में किया गया।वही सेंट्रल बैंक के मैनेजर सुधांशु शर्मा,जिओ साहिबगंज के प्रतिनिधि विनोत ठाकुर,टेकनो पब्लिक स्कूल के निदेशक कालिदास पाठक,आलोक भरतिया,रतन अग्रवाल,अशोक सरॉफ आदि ने बच्चों में पौधा वितरण किया।मीके पर सभी बच्चों को पर्यावरण रक्षा का संकल्प दिलाया गया।

छह माह से लंबित आयुष्मान मित्रों के मानदेय भुगतान की हुई समीक्षा

संवाददाता

साहिबगंज : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त श्री दीपक कुमार दुबे की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति, डीटीएफ व जिला आयुष्मान भारत की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित स्वास्थ्य योजनाओं निर्माण कार्यों भुगतान स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं व अन्य स्वास्थ्य संबंधी कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सिविल सर्जन द्वारा अवगत कराया गया कि पीएम -एसबीएचआईएम के अंतर्गत भुगतान की प्रक्रिया लंबित है। बताया गया कि उक्त भुगतान जिला परिषद के माध्यम से किया जाता है। और कार्यकारी एजेंसी जिला परिषद व संबंधित एजेंसी जिला अभियंता हैं। इस पर उपायुक्त ने उप विकास आयुक्त सिविल सर्जन को मामले का निष्पादन करते हुए एक सप्ताह के अंदर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।तालझारी प्रखंड में

भवन निर्माण कार्य से संबंधित भुगतान हो जाने की जानकारी दी गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि संबंधित संवेदक द्वारा 15 दिनों के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित अभियंता द्वारा संवेदक को नियमानुसार काली सूची ब्लैकलिस्ट में डालने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।बैठक में एम्बुलेंस मरम्मत से संबंधित प्राप्त विपत्रों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि संबंधित विपत्रों की मोटर वाहन निरीक्षक से जांच कराते हुए जांच प्रतिवेदन और अपने स्तर मंतव्य के साथ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। जिले के जिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पेयजल की कमी है।वहां आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उपायुक्त ने संबंधित प्रखंडों के चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पेयजल स्वच्छता प्रमंडल के सहायक अभियंता के माध्यम से



आवश्यक प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत कराएं ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मंडरो में एनटीपीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए एम्बुलेंस के संचालन हेतु वाहन चालक एवं उनके मानदेय के लिए राशि

उपलब्ध कराने से संबंधित प्रस्ताव की भी समीक्षा की गई। इस संबंध में उपायुक्त ने सिविल सर्जन का निर्देश दिया कि वाहन चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस, नियुक्ति पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।उपायुक्त ने सभी

संबंधित पदाधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्यों में समयबद्धता गुणवत्ता पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का निर्देश दिया। आयुष्मान भारत की समीक्षा बैठक के दौरान विगत छह माह से लंबित

आयुष्मान मित्रों के मानदेय भुगतान की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सदर अस्पताल के उपाधीक्षक को निर्देश दिया कि लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें, ताकि आयुष्मान मित्रों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।वहीं, सदर अस्पताल परिसर में अवस्थित पोस्टमार्टम हाउस के स्थानांतरण से संबंधित विषय पर भी चर्चा की गई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया कि स्पेशल डिवीजन के माध्यम से आवश्यक स्थल का निरीक्षण कर प्राक्कलन तैयार करते हुए प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत किया जाए, ताकि पोस्टमार्टम हाउस के स्थानांतरण की प्रक्रिया को नियमानुसार आगे बढ़ाया जा सके।बैठक में उप विकास आयुक्त श्री सतीश चंद्रा, सिविल सर्जन डॉ.रामदेव पासवान सभी प्रखंडों के चिकित्सा पदाधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

न्यूज ब्रीफ

सिग्मा एडवॉरंड सिस्टम्स ने रोल्स-रॉयस के साथ 1,600 करोड़ का लॉन्ग-टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया
हासिल

रांची : सिग्मा एडवांरंड सिस्टम्स ने रोल्स-रॉयस के साथ लॉन्ग-टर्म कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। यह कॉन्ट्रैक्ट सिग्मा की हाल ही में अधिग्रहित यूके सब्सिडियरी, लीसेस्टर स्थित ब्रोमफोर्ड प्रिंसीजन सॉल्यूशंस के जरिए हासिल हुआ है। यह एग्रीमेंट ब्रोमफोर्ड के अधिग्रहण से मिलने वाले रणनीतिक फायदे को दिखाता है और दुनिया की प्रमुख एयरोस्पेस मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) कंपनियों में से एक के साथ सिग्मा के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को और मजबूत करता है। लगभग 125 मिलियन पाउंड (करीब 1,600 करोड़) की कीमत वाला यह समझौता, हाल ही में रोल्स-रॉयस के साथ हुए लगभग 300 मिलियन पाउंड (करीब 3,800 करोड़) के लॉन्ग-टर्म समझौते पर आधारित है। इससे महत्वपूर्ण एयरोस्पेस प्रोग्राम्स में ग्रुप के प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और कंटेंट का दावरा बढ़ेगा। इन समझौतों से रोल्स-रॉयस की यूके सप्लायर्स चैन में सिग्मा की स्थिति काफी मजबूत होगी और साथ ही लंबे समय तक रेवेन्यू की संभावना भी बढ़ेगी। ब्रोमफोर्ड के अधिग्रहण से एयरो इंजन रिसर्स और केसिंग्स के साथ-साथ एडवॉरंड प्रिंसीजन मैन्युफैक्चरिंग में विशेषज्ञता रखने वाली मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं सिग्मा के साथ जुड़ी हैं। सिग्मा एडवॉरंड सिस्टम्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुनील कालींदिंडी ने कहा, यह समझौता इस बात का एक और मजबूत सबूत है कि भारत का प्रिंसिजन इंजीनियरिंग और डिफेंस-एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग बेस कितनी तरक्की कर चुका है। रॉल्स-रॉयस जैसी ग्लोबल ओईएम कंपनियां अब भारत की ओर न सिर्फ़ कम लागत के फायदे के लिए, बल्कि इंजीनियरिंग की गहराई, क्वालिटी और बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता के लिए भी देख रही हैं। ब्रॉमफोर्ड की यूके में मौजूद खास क्षमताओं और भारत में हमारे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क को मिलाकर, हम सच में एक ग्लोबल, डुअल-सोर्स सॉल्यूशन दे पा रहे हैं। इससे सिग्मा को जटिल इंजन कंपोनेंट्स का एक व्यापक पोर्टफोलियो सप्लायर्स करने में मदद मिलेगी। एग्रीमेंट के तहत, ब्रॉमफोर्ड, सिग्मा की इंडिया और यूके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में एयरोइंजन रिंग, केसिंग, लॉक प्लेट और दूसरे जरूरी इंजन स्ट्रक्चर बनाएगा, जिससे रोल्स-रॉयस के निदेशानुसार एक ज्यादा बड़ा डुअल-सोर्स सॉल्यूशन बनेगा।

नालागढ़ ब्लास्ट: एनआईए ने गिरफ्तार किए तीन और आरोपी, आतंकी नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही एजेंसी



नालागढ़: नालागढ़ पुलिस थाना परिसर में पहली जनवरी 2026 को हुए आईईडी विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में एनआईए द्वारा गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर छह हो गई है। एजेंसी अब हमले के पीछे की बड़ी साजिश, आरोपियों के आपसी संबंधों और पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है।

एनआईए के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श कंडोला, निवासी मोहल्ला सिरहिंदिया, राहों, जिला एस्सीबीएस नगर पंजाब, करनप्रताप, निवासी मोहल्ला रोटा, राहों तथा दिवाजोत सैनी, निवासी झंसी पार्क कंठलीन, नवांशहर रोड, राहों, जिला एस्सीएस नगर पंजाब के रूप में हुई है। तीनों आरोपी पहले से ही पंजाब के गढ़शंकर पुलिस थाना में दर्ज एफआईआर के मामले में गिरफ्तार थे। अब एनआईए ने इन्हें नालागढ़ आईईडी विस्फोट मामले में भी गिरफ्तार कर लिया है। नालागढ़ पुलिस थाना परिसर में एक जनवरी 2026 को सुबह करीब 9:40 बजे जांच अधिकारी के कमरे से सटी बाहरी दीवार के पास विस्फोट हुआ था। मामले में शुरूआत में नालागढ़ पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में जांच एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए ने 8 मई 2026 को मामला दोबारा दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत जांच शुरू की। इससे पहले एनआईए इस केस में महावीर कुमार उर्फ काका, अजय मेहरा और मनप्रीत सिंह उर्फ मणि को गिरफ्तार कर चुकी है। ये तीनों भी पंजाब पुलिस द्वारा एएसएसओसी मोहाली में दर्ज एक मामले में पहले से गिरफ्तार किए गए थे। आतंकी साजिश तो नहीं: एनआईए का कहना है कि ताजा गिरफ्तारियां नालागढ़ विस्फोट के पीछे की बड़ी आतंकी साजिश और व्यापक नेटवर्क का पता लगाने की दिशा में की गई हैं। जांच एजेंसी आरोपियों की सटीक भूमिका, उनके आपसी संपर्क, हमले में शामिल अन्य लोगों और नेटवर्क से जुड़ी तमाम कड़ियों की जांच कर रही है।

देश-विदेश

भारत करवा सकता है युद्ध का अंत, मुलाकात के दौरान ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान ने पीएम मोदी से की अपील

एजेंसी/ बिश्केक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से इतर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ बैठक की। इस बैठक में पेजेशकियान ने पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका ने अपने वादे को पूरा नहीं किया, इसके बावजूद ईरान एक अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। पेजेशकियान ने कहा कि इलाके में शांति और स्थिरता को मजबूत करने में भारत काफी मदद कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, पेजेशकियान ने कहा कि हम अब भी समझौते और आपसी समझ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा मानना ​​​​है



द सॉलिटेयर फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2026 अंतिम सप्ताह में प्रवेश

डिवाइन सॉलिटेयर्स के आकर्षक फेस्टिव ऑफर्स ने बढ़ाई खरीदारी की रौनक

रांची : द सॉलिटेयर फेस्टिवल ऑफ इंडिया डिवाइन सॉलिटेयर्स का प्रमुख एनुअल कस्टमर कैपेन आज यानी 1 अगस्त 2026 को देशभर में अपने विस्तृत पार्टनर ज्वेलर्स नेटवर्क के माध्यम से शुरू हुआ था और अब अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर रहा है। फेस्टिवल के समापन के करीब पहुंचने के साथ, डिवाइन सॉलिटेयर्स ने खास फेस्टिव ऑफर्स की घोषणा की है, जिससे ग्राहकों को इस त्योहारी सीजन में विशेष लाभ और आकर्षक रिवांड्स का आनंद उठाने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। टीएसएफआई 2026 के तहत डिवाइन सॉलिटेयर्स ने ग्राहकों के लिए नए और आकर्षक ऑफर्स पेश किए हैं, जो इस त्योहारी सीजन में खरीदारी को और खास बनाएंगे। 27 और 28 अगस्त को खरीदारी करने वाले ग्राहकों को उनके



सुनिश्चित उपहारों में विशेष अपग्रेड मिलेगा। इसके अलावा, जो ग्राहक अपने आभूषणों को व्यक्तिगत स्पर्श देना चाहते हैं, वे इन दोनों दिनों के दौरान बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने आभूषणों पर अपने नाम के शुरूआती अक्षर भी खुदवा सकेंगे। आमतौर पर इस तरह की नक्काशी के लिए 2,500 से 3,000 रुपये तक का शुल्क लिया जाता है, लेकिन इस विशेष फेस्टिव ऑफर के तहत यह सेवा ग्राहकों को नि:शुल्क प्रदान

की जाएगी।इन ऑफर्स का लाभ आपके शहर की निम्नलिखित दुकानों पर उठाया जा सकता है:कुलदीप संस ज्वेलर्स झ्र रांची-1, एसी मार्केट, चर्च कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, रांची 834001।प्रमाणित नेचुरल डायमंड सॉलिटेयर्स के इस रिटेल फेस्टिवल के माध्यम से एक महीने तक चलने वाले इस फेस्टिव में उपभोक्ताओं और ज्वेलरी रिटेलर्स को एक साथ जोड़ा जाता है। इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को प्रमाणित नेचुरल डायमंड सॉलिटेयर्स के साथ जीवन के खास पलों को यादगार बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही, यह पूरे भारत में डिवाइन सॉलिटेयर्स के रिटेल पार्टनर्स के लिए ब्रांड की दृश्यता बढ़ाने और स्टोर्स पर ग्राहकों की आवाजही बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

महिलाएं घर में रह कर बच्चे पालें, इमाम एसोसिएशन अध्यक्ष मौलाना रशीदी बोले देश में शरिया कानून जरूरी

एजेंसी/ तिरुवनंतपुरम: केरल के प्रमुख सुन्नी धर्मगुरु कांथापुरम एपी अबुबक्र मुसलियार के महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान के बाद देश में राजनीतिक और सामाजिक पारा चढ़ गया है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कांथापुरम के विचारों का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा है कि देश में जब तक इस्लामिक कानून (शरिया) लागू नहीं किया जाएगा, तब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं रह सकतीं। रशीदी ने स्वतंत्रता और समानता के नाम पर महिलाओं को वर्कफोर्स में शामिल करने पर सवाल उठाए और दावा किया कि इससे समाज में नैतिक पतन और बर्बादी बढ़ी है। रशीदी ने कहा कि यौन हिंसा और बलात्कार जैसे अपराधों को रोकने के लिए सख्त इस्लामिक सजा की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि जब तक सख्त कानून नहीं बनेंगे, तब तक महिला सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बनी रहेगी। रशीदी का तर्क है कि महिलाओं को घर के भीतर रहकर बच्चों का पालन-पोषण और गृहस्थी संभालनी चाहिए, जबकि पुरुषों को बाहर निकलकर कमाई करनी चाहिए और परिवार का पालन-पोषण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी के नाम पर महिलाओं को काम पर भेजने की होड़ ही उनके लिए असुरक्षा का कारण बन रही है।

सुभाष चंद्रा को एनसीएलटी से बड़ा झटका

22,006 करोड़ के लोन निपटारे पर रोक, संपत्ति ट्रांसफर करने पर भी पाबंदी

नई दिल्ली: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने मंगलवार को एसेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा से जुड़े दिवालिपायन मामले पर 25 अगस्त को दिए अपने आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही ट्रिब्यूनल ने सुभाष चंद्रा को गारंटर के तौर पर अपनी संपत्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ट्रांसफर करने से भी रोक दिया है।

मामले की सुनवाई कर रही तीन सदस्यीय पीठ के सदस्यों के बीच



आदेश को लेकर मतभेद सामने आने के बाद इसे एनसीएलटी की पांच सदस्यीय स्पेशल बेंच के समक्ष भेजा गया था। मंगलवार को स्पेशल बेंच ने मामले की सुनवाई शुरू की और कहा कि पहले के आदेशों में मतभेद था तथा कोई स्पष्ट बहुमत नहीं था, जिसे लागू किया जा सके।

स्पेशल बेंच ने पुराने आदेश के तहत 22,006 करोड़ से अधिक के लोन को करीब 6.26 करोड़ में निपटाने के फैसले पर रोक लगा दी।

इसके साथ ही सुभाष चंद्रा को अपनी संपत्तियां बेचने या किसी अन्य तरीके से ट्रांसफर करने से भी रोक दिया गया है। एनसीएलटी ने मामले से जुड़े सभी मामलों में दिवालिपायन की प्रक्रिया खत्म करने का रास्ता साफ हो गया था। एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा से जुड़े 22,006 करोड़ से अधिक के लोन का निपटारा करीब 6.25 करोड़ में करने का आदेश दिया था। हालांकि, ये लोन सुभाष चंद्रा के व्यक्तिगत लोन नहीं हैं। वह इन कर्जों के गारंटर हैं।

ऐसे में गारंटर के तौर पर उनके खिलाफ दिवालिपायन की कार्रवाई चल रही थी। पुराने आदेश के तहत करीब 6.25 करोड़ के भुगतान से इस मामले में दिवालिपायन की प्रक्रिया खत्म करने का रास्ता साफ हो गया था।

एनसीएलटी के पुराने फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि 22,006 करोड़ से ज्यादा के लोन का निपटारा महज करीब 6.25 करोड़ के भुगतान से कैसे किया जा सकता

है। इस फैसले को लेकर विवाद बढ़ने के बाद मामला स्पेशल बेंच के सामने पहुंचा।

अब पांच सदस्यीय स्पेशल बेंच ने पुराने आदेश पर रोक लगाकर मामले को नए सिरे से सुनने का रास्ता साफ कर दिया है। साथ ही सुभाष चंद्रा की संपत्तियों के ट्रांसफर पर रोक लगाकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि मामले की सुनवाई के दौरान संपत्तियों को हटया या बेचा न जा सके।

रांची : मिड-साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट (250 सीसी झ750 सीसी) में दुनिया की



लाइडर, रॉयल एनफील्ड ने आज भारत में क्लासिक350 गोरखा एडिशन लॉन्च करने की घोषणा की। गोरखा रेंजिमेंट की विरासत से प्रेरित, क्लासिक 350 का यह नया रूप साहस, अनुशासन और दृढ़ता की कई पीढ़ियों को सम्मान देता है, साथ ही मोटरसाइकिल के सदाबहार कैरेक्टर और असली राइडिंग अनुभव को भी बनाए रखता है।रॉयल एनफील्ड की डिजाइन फिलॉसफी पर आधारित, क्लासिक 350 का गोरखा एडिशन दुनिया की सबसे सम्मानित सैन्य रेंजिमेंटों में से एक, गोरखा रेंजिमेंट के बहादुर जवानों के सम्मान और प्रशंसा के प्रतीक के तौर पर तैयार किया गया है। क्लासिक 350 गोरखा एडिशन अपनी प्रेरणा को अपनी खास मौजूदगी के साथ दर्शाता है। खास 'गोरखा ग्रीन' रंग में तैयार, यह समृद्ध और प्रभावशाली रंग क्लासिक के मशहूर सिल्वूट को एक नई गहराई और पहचान देता है, जबकि मशहूर 'क्रॉसड खुकरी' वाला विशेष प्रतीक-चिह्न इसकी विशिष्ट पहचान बन जाता है। खास तौर पर इस एडिशन के लिए तैयार किए गए ये एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाते हैं जो गोरखाओं की भावना को गर्व के साथ दर्शाती है—अपनी अभिव्यक्ति में दमदार, अपनी

संजीव चौहान (एवीएसएम, वाईएसएम) ने कहा, गोरखा रेंजिमेंट की ताकत सिर्फ़ उसके इतिहास में ही नहीं, बल्कि हिम्मत, अनुशासन और सम्मान जैसे उन मूल्यों में भी है जिन्हें पीढ़ियों से कायम रखा गया है। यह देखना गर्व की बात है कि इस विरासत को रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गोरखा एडिशन के जरिए सम्मान दिया जा रहा है, जो गोरखा सैनिकों के जच्चे और परंपराओं को सम्मान और गरिमा के साथ श्रद्धांजलि देता है।अपनी विशिष्ट सीधी राइडिंग पोझिशन और परिष्कृत ख-सीरीज इंजन के साथ, क्लासिक 350 गोरखा एडिशन उसी विशिष्ट डिजाइन और राइडिंग अनुभव को बनाए रखता है, जिसने क्लासिक 350 को रॉयल एनफील्ड की सबसे प्रतिष्ठित मोटरसाइकिलों में से एक बनाया है और इसके क्लासिक ब्रिगेड के प्रेसिडेंट, लेफ्टिनेंट

होर्मुज में बारूद से टकराया सुपरटैंकर, विस्फोट के बाद लगी आग, बंद पड़ा इंजन, जहाजों को ईरान की वार्निंग

एजेंसी/ तेल अवीव: होर्मुज स्ट्रेट में एक सुपरटैंकर के दो समुद्री माइंस से टकराने के बाद उसमें भीषण आग लग गई। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी ने सोमवार को दावा किया कि जहाज ने होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी हिस्से में उस रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जिसे ईरान अनधिकृत और अवैध मानता है। इसी दौरान सुपरटैंकर दो माइंस से टकरा गया और पूरी तरह रुक गया। आईआरजीसी ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वाला सुपरटैंकर होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी रास्ते से गुजर रहा था। इसी दौरान वह दो समुद्री माइंस से टकराया। टक्कर के बाद जहाज में बड़े स्तर पर आग लग गई और उसे पूरी तरह रोकना पड़ा। हालांकि, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने जहाज का नाम, उसका झंडा,

कार्गो या चालक दल की जानकारी नहीं दी है। हादसे में किसी के हताहत होने की भी जानकारी सामने नहीं आई है।

आईआरजीसी ने दूसरे जहाजों को भी चेतावनी दी है। उसने कहा कि जो अन्य जहाज ईरान के बताए नैविगेशन नियमों का उल्लंघन करेंगे, उन्हें भी इसी तरह के अंजाम का सामना करना पड़ सकता है। ईरान ने शिपिंग कंपनियों से अमरीकी सेना के निदेशों का पालन नहीं करने को भी कहा है। होर्मुज स्ट्रेट में माइंस का खतरा ही अमरीका की हालिया सैन्य कार्रवाई के पीछे भी एक बड़ी वजह रहा है। अमरीका ने ईरान के लारक आईलैंड पर हमला किया था। अमेरिकी सेना के मुताबिक, लारक पर आईआरजीसी के दो लॉन्च

सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमरीका का दावा था कि ईरानी सेना इन लॉन्च सिस्टम के जरिए होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री माइंस डालने की तैयारी कर रही थी। अमेरिका ने कहा, शिपिंग के लिए होर्मुज खतरनाक: अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस गतिविधि को स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए तत्काल खतरा बताया था। अमरीका का कहना था कि उसने होर्मुज के अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट से पहले मौजूद माइंस को हटाने का काम पूरा किया था और ईरानी सेना दोबारा वहां माइंस डालने की तैयारी कर रही थी। अब एक सुपरटैंकर के दो माइंस से टकराने के ईरानी दावे ने होर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।



न्यूज़ IN ब्रीफ

टेंटा की बेटी ने हासिल की पीएचडी की उपाधि

मेदिनी नगर : हुसैनाबाद प्रखंड के टेंटा गांव निवासी पत्रकार एवं व्यवसायी शालिग्राम तिवारी की सुपुत्री संचिता गौड़ ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए पटना विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। पटना विश्वविद्यालय के प्रमाणपत्र के अनुसार संचिता गौड़ ने गृह विज्ञान विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) की डिग्री हासिल की है। उनकी यह उपलब्धि हुसैनाबाद क्षेत्र के लिए गौरव का विषय बनी है। पटना में आयोजित दीक्षांत समारोह में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सख्यद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) द्वारा संचिता गौड़ को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई।

संचिता की इस सफलता से उनके पैतृक गांव टेंटा सहित पूरे हुसैनाबाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है। पिता शालिग्राम तिवारी लंबे समय से पत्रकारिता एवं व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं और बिहार के रोहतास जिले के डेहरी आंन सोन में रहते हैं। बेटी की इस शैक्षणिक उपलब्धि को लेकर परिवार, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों में खासा उत्साह है।संचिता गौड़ की सफलता पर बीएचयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष बীরेंद्र सिंह, समाजसेवी उषेंद्र सिंह तथा पूर्व मुखिया धर्मराज सिंह उर्फ बैरिस्टर सिंह समेत कई गणमान्य लोगों ने बधाई दी है। लोगों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ग्रामीण परिवेश से निकलकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह मुकाम हासिल करना अन्य छात्र-छात्राओं के लिए भी प्रेरणादायक है।संचिता की सफलता ने एक बार फिर साबित किया है कि प्रतिभा और मेहनत के दम पर ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां भी शिक्षा के सर्वोच्च मुकाम तक पहुंचकर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन कर सकती हैं।

सोन नदी का जलस्तर बढ़ा, तटवर्ती गांवों में माइकिंग कर अलर्ट

हुसैनाबाद/हैदरनगर : सोन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए हुसैनाबाद और हैदरनगर क्षेत्र के तटवर्ती गांवों में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। जलाशयों से करीब दो लाख क्यूसेक अतिरिक्त पानी सोन नदी में पहुंचने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा है। हैदरनगर थाना क्षेत्र के सोन नदी से सटे सभी गांवों यथा-कवरा कला , परता एवं सजवन में पुलिस ने माइकिंग कर ग्रामीणों को अलर्ट किया है। थाना प्रभारी तंजीलूल मनान मनउव्वर ने बताया कि नदी के बीच बालू के टीलों पर खेती करने वाले किसानों, पशुपालकों और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर लौटने की सलाह दी गई है। इधर हुसैनाबाद के सोनपुरवा, देवरी खुर्द, देवरी कला, बुधुआ, बड़ेपुर और दंगवार समेत तटीय इलाकों में ग्रामीणों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जलस्तर में अचानक वृद्धि की आशंका को देखते हुए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है।

लगাতार वारिश से यातायात और जनजीवन अस्तव्यस्त



मुरी : आज सुबह से ही करीब तीन घंटे के वर्षा ने मुरी गोला रोड सिंगपुर सड़क के गडबड़े तलाब में तब्दिल हो गया है। वाहन चालक या दो पहिया वाहन, टेम्पू, स्कुली बस को गडडा पता नहीं चल पा रहा है। इस सड़क पर तीन बड़े बड़े गडडे है जहाँ से गाडियों असंतुलित होकर पार कर रही है। पहले यह रोड इतना खराब नहीं था, जब से फोर लाइन सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ है तब से सड़क की हालत और बिगड़ गई है। स्कूलों के बच्चे पैदल पार ही नहीं हो पा रहे है इस रास्ते में तीन अस्पताल भी है जिसके चलते भीड़ भाड़ बना हुआ रहता है। सोलह- सोलह चक्के वाली बड़ी बड़ी गाडियों का आना जाना है। चारों तरफ पानी पानी है। हिण्डालको जाने का वाईपास रास्ता बर्षा से कीचड़ मय है। इसमें भी जगह जगह गडडे है। इस रास्ते में मुरी थाना है। ज्यादातर हिण्डालको के काम से गाडियाँ आती जाती रहती है। बगल में स्वर्ण रेखा नदी बहती है उसमें भी जलस्तर बढ़ा हुआ है।

जेकेएस कॉलेज मानगो में रक्तदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

जमशेदपुर: जेकेएस कॉलेज, मानगो में एनएसएस इकाई-1 द्वारा वॉलेंट्री ब्लड डोन्स एसोसिएशन के सहयोग से मंगलवार को रक्त जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को रक्तदान के महत्व, प्रक्रिया, पात्रता और इससे जुड़ी भ्रांतियों के प्रति जागरूक करना था।जमशेदपुर ब्लड बैंक के सुनील मुखर्जी ने स्वीच्छिक रक्तदान को सामाजिक जिम्मेदारी बताते हुए युवाओं से नियमित रक्तदान की अपील की। जमशेदपुर हीमोफीलिया सोसाइटी के संस्थापक प्रदीप घोषाल ने हीमोफीलिया मरीजों के लिए रक्त एवं आवश्यक रक्त-घटकों की निरंतर उपलब्धता को महत्वपूर्ण बताया।[प्राचार्य डॉ। मोहित कुमार ने कहा कि रक्तदान मानव जीवन बचाने का महान कार्य है। उन्होंने विद्यार्थियों से जागरूकता का सदेश समाज तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में डॉ। संदिता श्रीवास्तव, डॉ। संजय सिन्हा समेत शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी और एनएसएस स्वयंसेवक मौजूद रहे। विद्यार्थियों को 2 सितंबर को कॉलेज परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया।

एसआईआर में 4145 लाख वोटरों के नाम पते में गलती, जाएगी नोटिस

धनबाद : एसआईआर को लेकर मैपिंग का काम समाप्त होने के बाद प्रारूप वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया गया। प्रारूप मतदाता सूची में शामिल 1652203 वोटरों में से 445901 वोटरों के नाम, उम्र, पिता के नाम समेत अन्य तरह की विसंगतियां पाई गई है। अब इन वोटरों को जिला निर्वाचन विभाग की ओर से नोटिस भेजी जा रही है। जिन वोटरों को नोटिस भेजी जा रही है वह इन गलतियों को सुधारने के लिए दस्तावेज लेकर सुनवाई में शामिल होंगे। जिला निर्वाचन विभाग ने जिले के 50 अधिकारियों को सुनवाई के काम में लगाया है। नगर निगम, जिला प्रशासन से लेकर लगभग सभी सरकारी विभाग के अधिकारी और कर्मी एसआईआर की सुनवाई में लगे हुए हैं। चार-पांच बूथों को मिलाकर एक जगह केंद्र बनाया गया है, वहीं अधिकारी बैठकर सुनवाई कर रहे हैं। लोग वोटर लिस्ट में हुई गलतियों को सुधारने के लिए पहुंच रहे हैं।

एनपीयू में कथित गड़बड़ी के खिलाफ शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन, कुलपति का फूंका पुतला

संवाददाता

पलामू : नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्र संगठनों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। यह आंदोलन आपसू, एनएसयूआई और जेसीएम ने शुरू किया है। आंदोलन के पहले चरण में सोमवार को छात्रों ने नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह का प्रतीकात्मक पुतला फूँका। दरअसल हाल में ही यूनिवर्सिटी के ऑडिट रिपोर्ट में कई चॉकाने वाले खुलासे हुए हैं और सूचना के अधिकार के तहत छात्रों ने ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी ली है।

गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन ऑडिट रिपोर्ट में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्र संगठन आंदोलन कर रहे हैं और प्रतिदिन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए मामलों को उजागर कर रहे है। आंदोलन कर रहे छात्रों ने कहा कि यूनिवर्सिटी किसी की निजी संपत्ति नहीं है बल्कि सार्वजनिक संपत्ति है और इससे हजारों

छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है।

इससे पहले रविवार को छात्रों ने यूनिवर्सिटी में हुई गड़बड़ियों को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका (ढक्छ) दायर करने की योजना की घोषणा की। अपने आंदोलन के जरिए छात्र वितीय गड़बड़ियों के खिलाफ कार्रवाई, यूनिवर्सिटी के द्वारा खरीद और भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने, गड़बड़ियों में शामिल लोगों के खिलाफ त्रमम्र दर्ज करने और छात्रों से जुड़े प्रशासनिक मामलों के जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं।

करोड़ों का घोटाला पकड़ा गया: छात्र राहुल दुबे आंदोलन कर रहे छात्र राहुल दुबे ने बताया कि यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और ऑडिट रिपोर्ट में करोड़ों का घोटाला पकड़ा गया। छात्र नेता कमलेश पांडेय ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पकड़ी गई है जिसे लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं।



नीरु पहाड़ी में बारिश के बीच काल बना अज्ञात वाहन, युवक की मौत

सड़क सुरक्षा बैठकों के बावजूद रफ्तार पर लगाम नहीं, बुझ गया एक और घर का चिराग

संवाददाता

कोडरमा : डोमचांच थाना क्षेत्र के नीरू पहाड़ी के समीप सोमवार देर रात मूसलाधार बारिश के बीच हुए सड़क हादसे में 33 वर्षीय युवक प्रीतम पटेल की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक गिरिडीह जिले के राजनघरवार निवासी स्व। मुन्ना राउत के पुत्र थे। वे झुमरी तिलैया में किराए के मकान में रहकर स्मार्ट बाजार में काम करते थे। जानकारी के अनुसार प्रीतम सोमवार को अपने पैतृक गांव राजनघनवार गए थे। देर रात बाइक से झुमरी तिलैया लौटने के दौरान



नीरू पहाड़ी के पास किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि प्रीतम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही डोमचांच थाना प्रभारी अभिमन्यु कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कोडरमा भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मृतक के परिजनों

की पहचान कर उन्हें सूचना दी गई है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। मंगलवार सुबह परिजन सदर अस्पताल पहुंचे तो शव देखते ही चीख पड़ी। बताया गया कि प्रीतम के पिता का करीब एक वर्ष पूर्व निधन हो चुका है। उनके पीछे विधवा मां, पत्नी और छोटी बेटी रह गई हैं। सड़क

सुरक्षा पर सवाल: स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार कोडरमा में लगातार हादसों की बड़ी वजह बन रही है। प्रशासन की ओर से हर महीने सड़क सुरक्षा को लेकर बैठकें और निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन सड़कों पर रफ्तार पर प्रभावी अंकुश अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। सवाल यही है कि आखिर कब तक लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण घरों के चिराग बुझते रहेंगे?

बेहतर प्रदर्शन कर बीसीसीएल को मुनाफे में लाएं : तरुण कपूर

धनबाद : बीसीसीएल के दो दिनी दौर पर सोमवार को धनबाद पहुंचे प्रधानमंत्री (पीएमओ) के सलाहकार तरुण कपूर ने बीसीसीएल अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कंपनी के प्रदर्शन को सुधारने और मुनाफे में लाने का टास्क दिया। सीबीएम प्रोजेक्ट, मुनीडीह लांगवाल प्रोजेक्ट एवं एना फायर प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। बीसीसीएल मुख्यालय में बैठक के दौरान कपूर ने कहा कि बीसीसीएल देश के इस्पात क्षेत्र की कीकिंग कोयला आवश्यकता की पूर्ति में रणनीतिक भूमिका निभाती है। उपलब्ध संसाधन का वैज्ञानिक एवं अधिकतम उपयोग करते हुए कंपनी को अधिक दक्ष, तकनीक रूप से सक्षम, सुरक्षित एवं पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी संस्था के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने झरिया के अनिन प्रभावित एवं उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सुरक्षा तथा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। कपूर ने क्षेत्रीय महाप्रबंधकों के साथ संवाद कर क्षेत्रीय स्तर पर सामने आ रही विभिन्न परिचालन

एवं प्रशासनिक चुनौतियों, उनके कारणाें तथा उनसे निपटने के लिए संबंधित क्षेत्रों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने प्रभावी क्षेत्रीय पहलों के साझा करने, अंतर-विभागीय समन्वय मजबूत करने तथा स्थानीय स्तर पर आने वाली बाधाओं के समयबद्ध समाधान से उत्पादन एवं परिचालन दक्षता में और सुधार लाने पर बल दिया। वहीं सीबीएम (कोल बेड मोथेन) दोहन पर भी जोर दिया। कहा कि कोयला खदानों से मीथेन गैस के निकाले जाने के बाद दुर्घटना में कमी आएगी। गैस का उपयोग घरों के साथ वाहन चलाने के लिए गैसीय ऊर्जा (सीएनजी) के रूप में भी उपयोग किया जा सकेगा। बताया गया कि अक्टूबर 27 तक सीबीएम परियोजना पूरी हो जाएगी। बैठक में बीसीसीएल की ओर से सतत विकास, विविधीकरण एवं स्वच्छ ऊर्जा के अंतर्गत मुनीडीह एवं महुदा सब-बेसिन स्थित दो सीबीएम ब्लॉकों, इको-पार्क, वनीकरण, धूल नियंत्रण, कोल नीर परियोजना तथा अन्य पर्यावरणीय पहलों की स्थिति प्रस्तुत की गई।

पुनर्वास को पारदर्शी और मानवीय दृष्टिकोण से आगे बढ़ाएं

धनबाद/पुटकी/झरिया : पीएमओ के सलाहकार तरुण कपूर ने सोमवार को बीसीसीएल की प्रमुख परियोजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा की और उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कोल बेड मीथेन (सीबीएम) ब्लॉक-एक परियोजना, मुनीडीह 16 सीम लॉन्गवॉल परियोजना तथा कुसुंडा क्षेत्र स्थित एना अनिन परियोजना का दौरा किया। उच्च जोखिम वाले स्थलों से प्रभावित परिवारों से संवाद किया। मौके पर कपूर ने कहा कि पुनर्वास कार्य को पारदर्शी, संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाएं। लोगों की समस्याओं एवं चिंताओं को करीब से जाना। इधर बैठक में निदेशक (तकनीकी/संचालन) संजय कुमार सिंह ने बीसीसीएल के परिचालन एवं रणनीतिक परिदृश्य की विस्तृत प्रस्तुति दी। इस दौरान बीसीसीएल में अग्रवाई जा रही लॉन्गवॉल माइनिंग, हाईवॉल माइनर एवं एसडीएल जैसी तकनीकों के साथ-साथ सरफेस माइनर एवं कंटीन्यूअस माइनर जैसी आधुनिक तकनीकों के विस्तार, झरिया कोलफील्ड के ओपनकास्ट ब्लॉकों के पुनर्गठन तथा बंद खदानों को एमडीओ/रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के माध्यम से पुनर्विकसित करने की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया। वाशरी प्रदर्शन, आगामी वाशरी क्षमता विस्तार, कोयला धुलाई तथा कोयला गुणवत्ता सुधार से संबंधित पहलों की भी शामिल किया गया।

आयात निर्र्भरता कम करेगा घरेलू कोयला

प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर बल दिया कि आधुनिक भूमिगत खनन तकनीक और सीबीएम संसाधन का समन्वित उपयोग देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने, घरेलू कोकिंग कोयला उपलब्धता बढ़ाने तथा आयात पर निर्र्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। सुरक्षित, पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी एवं सतत खनन पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया गया। कपूर ने परियोजना में मानक संचालन प्रक्रियाओं के कड़ाई से अनुपालन, सुरक्षित एवं समयबद्ध कमीशनिंग तथा आधुनिक यंत्रकृत खनन तकनीक के प्रभावी उपयोग पर विशेष जोर दिया। समीक्षा बैठक में कोल इंडिया चेयरमैन बी। साईराम, सीएमडी बीसीसीएल मनोज कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव (वस्त्र मंत्रालय) अलकनंदा दयाल; परियोजना सलाहकार, कोयला मंत्रालय आलोक कुमार सिंह, निदेशक (मानव संसाधन) मुरली कृष्ण रमैया, निदेशक (तकनीकी/संचालन) संजय कुमार सिंह, निदेशक (वित्त) राजेश कुमार, निदेशक (तकनीकी/परियोजना एवं योजना) राजीव कुमार सिन्हा, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों सहित क्षेत्रीय महाप्रबंधक, मुख्यालय के महाप्रबंधक/विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुनीडीह भूमिगत खदान का किया निरीक्षण मुनिडीह परियोजना का दौरा कर आधुनिक खनन तकनीक, लॉन्गवॉल उत्पादन प्रणाली

तथा मीथेन गैस निष्कर्षण परियोजना का जायजा लिया। उन्होंने करीब 500 मीटर भूमिगत जाकर लोकोमोटिव के माध्यम से लॉन्गवॉल फेस का निरीक्षण किया और कोयला कटिंग एवं उत्पादन प्रक्रिया को करीब से देखा। इस दौरान उन्होंने खदान कर्मियों से बातचीत कर उनके कार्य एवं अनुभवों की जानकारी ली। सीबीएम प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। मौके पर प्रभा एनर्जी के प्रोजेक्ट हेड राजीव लोचन, वाइस प्रेसिडेंट सुनील सिंह,असस्टेंट कुमार ने किया। मौके पर परियोजना पदाधिकारी डॉ सन्नी राव ने पावर प्रेजेंटेशन दी। एजीएम सुनील कुमार पांजा,पीओ सन्नी राव,एरिया सेफ्टी ऑफिसर, विद्या शंकर बर्णवाल एरिया इंजीनियर प्रभात रंजन झा,कोलियरी इंजीनियर मनीष कुमार,इंडु का डायरेक्टर श्री सुब्रमण्यम रेड्डी कर्मचारी उपस्थिति थे।

पीएमओ के सलाहकार तरुण कपूर आज झरिया पुनर्वास पर अहम बैठक करेंगे। झरिया पुनर्वास पीएमओ की प्राथमिकता सूची में है। बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीसीसीएल-जेआरडीए के अलावा कई अन्य संबंधित विभाग मसलन रेलवे, एनएचआई, टेलीकॉम आदि के अधिकारी मौजूद रहेंगे।

पलामू के महेंद्र विश्वकर्मा की खोज में नेपाल पहुंचे परिजन

25 अगस्त की रात आखिरी बार हुई थी पत्नी से बात

संवाददाता

पलामू : जिला के हैदरनगर प्रखंड (थाना मोहम्मदगंज) क्षेत्र के बडंडा बरवाडीह गांव के 50 वर्षीय महेंद्र विश्वकर्मा पिछले 6 दिन से लापता हैं। महेंद्र नेपाल के बाणेश्वर में एक हाइड्रो पावर प्लांट में नौकरी करते हैं। 25 अगस्त के बाद से उनका परिवार से कोई संपर्क नहीं

हो पाया है।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पलामू जिला प्रशासन और पुलिस दोनों ने उनकी खोज के लिए युद्धस्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं महेंद्र विश्वकर्मा की पत्नी कलावती देवी ने बताया कि महेंद्र विश्वकर्मा के छोटे भाई, पुत्र समेत 5 लोग उन्हें दूढ़ने रविवार को नेपाल के बाणेश्वर पहुंच चुके हैं।

वह अपने स्तर से पता लगाने में जुटे हैं लेकिन अब तक उनका पता नहीं चल सका



है। महेंद्र विश्वकर्मा पिछले दो माह से नेपाल के बाणेश्वर स्थित हाइड्रो पावर

